सरदार वल्लभ भाई पटेल

[illegible]

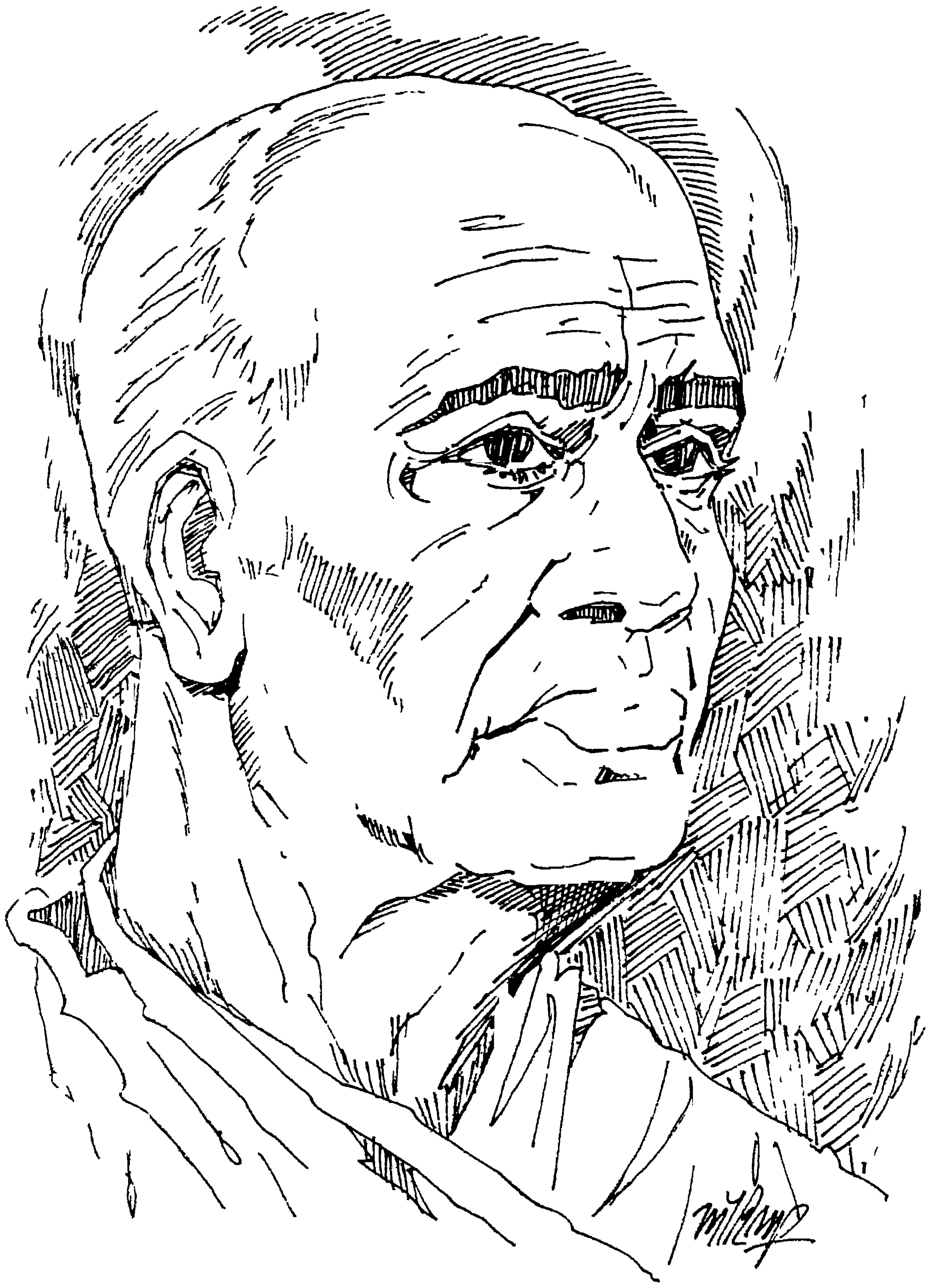

सरदार
वल्लभ भाई पटेल

लेखक
प्रयंक कुमार
चित्रांकन
शंकर नायक

प्रकाशक
कला साहित्य संस्थान
430, प्रथम तल, महाराम मोहल्ला
शाहदरा, दिल्ली-32

प्रकाशक	**कला साहित्य संस्थान** 430, प्रथम तल, महाराम मोहल्ला शाहदरा, दिल्ली-110032
मूल्य	150 00 रुपये
सर्वाधिकार	सुरक्षित
सस्करण	सन् 2002
आवरण	एस के ग्राफिक्स, दिल्ली-110032
शब्द-सयोजन	एस के कम्प्यूटर्स, दिल्ली-110032
मुद्रक	एस एन प्रिटर्स, दिल्ली-110032

अनुक्रम

सरदार पटेल	7
शिक्षा	10
बड़ोदा हाईस्कूल में	11
गांधी जी से भेंट	25
खेड़ा सत्याग्रह	28
काला कानून	30
असहयोग आन्दोलन	32
बारडोली का सत्याग्रह	36
सरदार पटेल और राष्ट्रीय आंदोलन	42
डांडी यात्रा	46
समाजवादियों में मतभेद	60
सुभाषचन्द्र बोस से मतभेद	64
अन्तरिम सरकार तथा भारत विभाजन	78
रियासतों का विलय	93

सरदार पटेल

ससार मे सदैव ऐसे महापुरुष हुए है जिन्होने इतिहास मे अपना नाम जोडा। इतिहास पर हम जब भी अपनी दृष्टि डालते है तो हम देखते है कि भारतभूमि पर समय-समय पर अनेक महापुरुषो ने जन्म लिया, जिन्होने भारतवर्ष का गौरव बढाया तथा भारत का शीश कभी झुकने नही दिया। इन बडे नेताओ तथा देशभक्तो ने अपने बलिदान और कर्त्तव्य से भारत को विदेशी दासता से मुक्त कराया।

परिचय

ऐसे ही एक देशभक्त ने 31 अक्टूबर, 1875 ई॰ को भारत के गुजरात प्रान्त मे जन्म लिया। बालक का नाम वल्लभभाई रखा गया। बालक के माता-पिता गुजरात के पेटलाद ताल्लुका के गाव करमसद के निवासी थे।

गुजरात मे कुरमी जाति की दो उपजातिया लवा और कदवा है। ये अपने को श्री रामचन्द्र के पुत्र लव और कुश के वशज बताती है।

वल्लभ के पिता का नाम झवेरभाई था। यह एक साधारण कुरमी किसान थे। ये खेती-बाडी करके अपना काम चलाते थे। बालक वल्लभ को भी कभी-कभी ये अपने साथ ले जाते थे।

बालक अपने पिता के काम मे हाथ बटाता था और अपने पहाडे भी वही याद करता था।

एक दिन पिताजी हल चला रहे थे। पटेल उनके पीछे अपना काम करते हुए पहाड़े भी स्मरण कर रहे थे। बालक पहाड़े याद करने मे इतना मग्न था कि उसके पैर मे डाव का काटा चुभ गया तो भी उसे पता नही चला। वह अपना काम करते हुए निरन्तर आगे बढ़ रहा था।

अचानक पिता की दृष्टि बालक के पैर की ओर गई। पैर से रक्त निकलता देखकर वे दग रहे गए। पिता ने बालक की दृढता को सराहा और पुत्र के पैर मे से काटा निकालकर उस पर काड वृक्ष की पत्तिया रगड दी, जिससे खून बहना बन्द हो गया।

पिता ने पुत्र को महान व्यक्ति बनने का आर्शावाद भी दिया।

वल्लभ के पिता झवेरभाई भी बडे देशभक्त थे। कहते है जब 1857 मे भारतीय स्वतन्त्रता-सग्राम चल रहा था तो झवेरभाई ने अपना हल और फावडा फेंक दिया था और महारानी झासी के पास युद्ध मे भाग लेने चले गए थे। जब इनका विद्रोह असफल हो गया तो झवेरभाई अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर घूमते-फिरते थे। इन्होने भी युद्ध मे बडी वीरता दिखाई थी। अन्त मे ये पकडे गए और इनको जेल मे डाल दिया गया। इन्दौर के राजा मल्हारराव ने उनको अपने राजभवन मे कैद कर लिया।

एक दिन मल्हारराव जेल के समीप बैठे हुए शतरज खेल रहे थे। जेल की सलाखो से झवेरभाई भी बडे ही ध्यान से शतरज देख रहे थे। खेल के बीच राजा एक ऐसी चाल चलने लगा जिससे उसकी हार निश्चित थी। झवेरभाई ने राजा को टोक दिया और दूसरी चाल चलने को कहा। राजा ने उसका कहना मान लिया और राजा जीत गया। राजा झवेरभाई की योग्यता पर बहुत प्रसन्न हुआ और उसे जेल से छोडने की आज्ञा दे दी। तीन साल बाद वह अपने गाव वापस आए।

वल्लभभाई पटेल के वडे भाई का नाम विट्ठलभाई पटेल था। वह भी प्रसिद्ध देश भक्त थे तथा भारतीय विधान परिषद जो अंग्रेजी राज्य के समय बनी थी, वे सभापति बने थे। पटेल की मा धार्मिक विचारो वाली थी। जिसका प्रभाव वल्लभ के पूरे परिवार पर पडा।

शिक्षा

गाव की सातवी कक्षा तक गुजराती मे ही पढाई होती थी। पटेल ने भी अपने गाव के स्कूल मे ही पढना आरम्भ किया। पटेल को यह स्कूल पसन्द नही था। वे किसी अंग्रेजी स्कूल मे पढना चाहते थे। इन्होने सातवी श्रेणी पास कर ली। इसके उपरान्त पाचवी श्रेणी तक अंग्रेजी भी एक प्राइवेट स्कूल मे पास की। अब पटेल का मन इन विधालयो से ऊव गया था। अतः वे पेटलाद ताल्लुका मे आ गए और वही पर अपनी पढाई आरम्भ कर दी।

वल्लभ ने अपना जीवन अत्यन्त ही सादगी से आरम्भ किया। वल्लभ पढाई मे अपना अधिक नाम नही कर सके। वल्लभ अपने गाव करमसद से एक सप्ताह का भोजन लेकर पेटलाद जाते थे। गाव से वह पैदल ही पेटलाद पहुचते थे। गाडी मे नही जाते थे और इस तरह इन्होने बचत करना भी बचपन मे ही सीख लिया था।

अब वल्लभभाई नडियाद हाईस्कूल मे पढना शुरू कर दिया। वल्लभभाई स्वाभिमानी थे अत स्कूल मे ये विद्यार्थियो के नेता बन गए। यदि कोई अध्यापक कोई अनुचित कार्य करता तो यह सहन नही करते थे और स्कूल मे तुरन्त ही हडताल करवा देते। जैसे विद्यार्थियो की भलाई के लिए ये जान देने को तैयार रहते थे, वैसे विद्यार्थी भी इनका कहना मानते थे।

एक बार स्कूल मे एक अध्यापक ने एक बालक को थोडी-सी भूल के कारण स्कूल से निकलवा दिया। वल्लभ को जब यह पता चला तो उन्हे क्रोध हो आया और उन्होने स्कूल मे हडताल करवा दी। हड़ताल कई दिन चली। अन्त मे अध्यापक ने अपनी भूल स्वीकार कर ली और वल्लभ ने भी हडताल समाप्त कर दी। इस घटना से वल्लभ को विद्यार्थी अपना सरदार मानते थे। इसके उपरान्त एक घटना और घटी।

नडियाद स्कूल के अध्यापक ने स्कूल मे पुस्तको की एक दुकान खोल रखी थी। विद्यार्थियो पर यह अध्यापक पुस्तके खरीदने के लिए अनुचित दबाव डाला करता था। वल्लभभाई को यह अन्याय सहन नही हुआ। वल्लभभाई ने पूर्ण बहिष्कार करा दिया। अन्त मे अध्यापक को झुकना पडा और उसे अपनी दुकान भी बन्द कर देनी पडी।

बड़ौदा हाईस्कूल में

अब वल्लभ नडियाद हाईस्कूल छोडकर बडौदा (वदोदरा) के हाईस्कूल मे प्रविष्ट हो गए। वल्लभ को सस्कृत कठिन लगती थी अत इन्होने गुजराती भाषा ही पढना उचित समझा।

उस समय श्री छोटेलाल वहा गुजराती पढाते थे। इनको सस्कृत बडी प्रिय थी। उनकी इच्छा थी कि सभी विद्यार्थी सस्कृत पढे। जब वल्लभ स्कूल मे दाखिल हुए तो उन्होने वल्लभ से कहा, 'आइए महापुरुष। आप सस्कृत छोडकर गुजराती ले रहे है लेकिन सस्कृत के बिना गुजराती शोभा नही देती।' सस्कृत के उन्होने कई लाभ गिना दिए।

यह सुनकर पटेल तनिक भी नही घबराए और उन्होने तुरन्त

ही उत्तर दिया, 'यदि सभी विद्यार्थी संस्कृत ही पढने लगे तो फिर आप गुजराती किसको पढाएगे।' गुरुजी को यह उत्तर सुनते ही आक्रोश आ गया तथा उन्होने बालक को पिछली बेंच पर खडा होने का दण्ड भी सुना दिया। मास्टर जी ने वल्लभ को शरारती बालक समझकर तग करना आरम्भ कर दिया। उनके तग करने का ढग भी निराला ही था। वह प्रतिदिन वल्लभ को घर से पहाडे लिखकर लाने के लिए कहने लगे।

कुछ दिनो तक तो वल्लभ यह सजा चुपचाप सहन करते रहे। परन्तु प्रतिदिन पहाडे लिखकर लाने की आज्ञा अब उन्हे असह्य हो गई थी। उन्होने इसका विरोध करने की योजना बनाई।

गुजराती मे पहाडे शब्द को पाडे भी कहते है जिसका अर्थ गाय-भैंस का बच्चा भी होता है।

एक दिन मास्टर ने पूछा, 'पाडे लिखकर लाए हो या नही?' पटेल ने उत्तर दिया, 'मास्टर जी, पाडे लाया तो था परन्तु वे स्कूल के दरवाजे पर ही भिड करके भाग गए।' मास्टर को पटेल के उत्तर पर बहुत क्रोध हो आया। मास्टर ने दूसरे दिन के लिए घर से दो सौ पहाडे लिखकर लाने के लिए आज्ञा दे दी।

बालक दूसरे दिन स्कूल आया। मास्टर साहब ने पहाडे दिखाने को कहा। पटेल ने तुरन्त अपनी कॉपी आगे बढा दी। उस पर लिखा था—दो सौ पहाडे।

मास्टर का पारा गर्म हो गया। उन्होने तुरन्त ही वल्लभ की शिकायत प्रधानाध्यापक के पास कर दी। प्रधानाध्यापक ने आपको बुलाया और आपसे घटना का विवरण पूछा। वल्लभ ने पूरी कथा साफ-साफ सुना दी। आपको कुछ सजा न मिली। आपके और मास्टर के बीच एक दरार पड गई।

ठीक इसके तीन मास बाद वल्लभभाई एक दूसरे शिक्षक से

टकरा गए। फिर शिकायत प्रधानाध्यापक के पास गई। प्रधानाध्यापक ने वल्लभ को स्कूल से निकालने का आदेश दे दिया।

अब वल्लभ नडियाद आ गए। तब वल्लभ की आयु लगभग 22 वर्ष थी। यहीं रहकर इन्होंने सन् 1897 में किसी तरह मैट्रिक परीक्षा पास की। क्योंकि पढ़ने-लिखने में पटेल होशियार नहीं थे।

वल्लभ के पिता धनी नहीं थे। अत वे वल्लभ को आगे पढ़ाने में असमर्थ थे। वल्लभ भी और पढ़ना नहीं चाहते थे। उनकी इच्छा तो बेरिस्टर बनने की थी। अत उन्होंने अपने कदम इसी लक्ष्य की ओर बढ़ाने शुरू कर दिए।

वल्लभ विद्यार्थी-जीवन में ही अंग्रेजों की ओर आकर्षित होने लगे थे। उनको यह आभास हो गया था कि अंग्रेज बहुत अच्छे तथा अक्लमन्द व्यक्ति हैं। वे उनके देश में जाकर पढ़ने को लालायित होने लगे। परन्तु पटेल के पास धन नहीं था अत वे विवश हो गए। उनके हृदय में विलायत जाकर बैरिस्टरी की शिक्षा प्राप्त करने की प्रबल इच्छा थी। परन्तु वे कहीं से भी पैसे का प्रबन्ध करने में असमर्थ रहे और उन्होंने अब दृढ़ निश्चय किया कि वे स्वयं धन कमाकर ही विलायत पढ़ने के लिए जाएंगे। धन के अभाव के कारण वल्लभभाई पढ़ाई आगे जारी न रख सके थे। परन्तु अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के सहारे इन्होंने तीन वर्षीय जिला मुख्तारी का कोर्स घर पर रहकर अच्छे अंकों से सन् 1900 में उत्तीर्ण किया।

अब वल्लभ को धन कमाने की चिन्ता सवार हुई। वे अपने मित्र काशीभाई के यहां गए और अपनी योजना को कार्य-रूप में परिवर्तित करने लगे।

अपने मित्र के यहां रहते हुए पटेल की कांख में फोड़ा हो गया। बहुत इलाज किया गया, परन्तु फोड़ा ठीक नहीं हुआ। अन्त

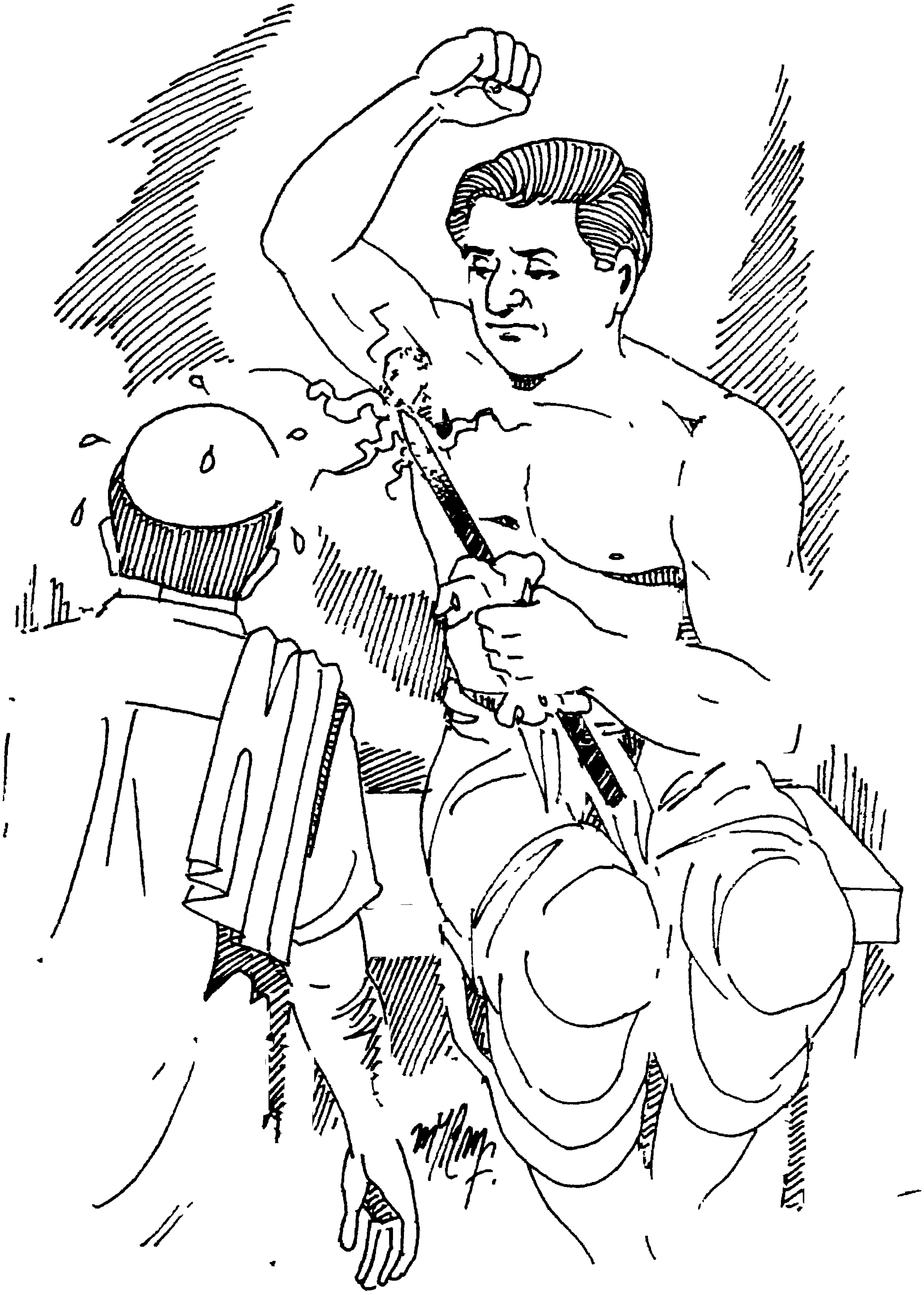

मे यह निश्चित हुआ कि फोडे को चीरा लगवा दिया जाए। नाई आया। नाई ने चीरा के वदले फोडे को गर्म सलाखो से जलाना ठीक वताया। सलाखे गर्म की गई। नाई फोडे को जलाने से घवरा गया। पटेल ने यह भाप लिया और उसने गर्म सलाखो से स्वय ही फोडे को जला दिया। वल्लभ इससे तनिक भी नही घवराए। देखने वाले वल्लभ की सहनशक्ति को देखकर हैरान हो गए।

अपने मित्र काशीभाई के पास रहते हुए इन्होने मुख्तारी पास कर ली और गोधरा मे ही वकालत करने लगे। इनके भाई विट्ठलभाई भी गोधरा मे ही वकालत करते थे और कुछ समय पूर्व ही वे बोरसद गए थे। वल्लभभाई ने उनकी जान-पहचान का भी लाभ उठाया। विट्ठलभाई ने वल्लभ को अपने साथ काम करने का सन्देश भेजा, परन्तु वल्लभ नही माने। गोधरा मे वल्लभ के पास कुछ भी सामान नहीं था। अत इन्होने कर्ज लेकर थोडा-थोड़ा सामान इकट्ठा किया और वडी तगी के साथ अपने जीवन की शुरुआत की। वल्लभभाई का विवाह सन् 1893 मे झवेरबा के साथ हुआ था। विवाह के समय उनकी आयु 18 वर्ष थी। सन् 1903 मे उनकी पत्नी ने एक वेटी को जन्म दिया जिसका नाम मणिबेन रखा गया। 28 नवम्वर, सन् 1905 मे उन्हे पुत्ररत्न प्राप्त हुआ। पुत्र का नाम रखा गया डाह्याभाई। परम्परा के अनुसार दोनो बच्चो का जन्म ननिहाल मे हुआ।

इन्ही दिनो गोधरा मे प्लेग फैल गया। कचहरी के किसी क्लर्क के लडके को भी प्लेग ने दवा लिया। उसको बुखार के साथ-साथ एक गिल्टी भी निकल आई। वल्लभ ने उस लडके की दिन-रात सेवा की, परन्तु वच नही सका।

सेवा करते-करते वल्लभ को भी प्लेग हो गया परन्तु भगवान की कृपा से वल्लभ शीघ्र ही ठीक हो गए।

जब वल्लभ को प्लेग हो गया तो उन्होंने अपनी पत्नी को करमसद भेजा दिया। पति तो ठीक हो गए, परन्तु पत्नी को प्लेग हो गया।

वल्लभ को पत्नी की बीमारी का पता चला तो वे उस गाव से इलाज के लिए बम्बई ले आए। वल्लभ पत्नी को बम्बई छोडकर स्वय गोधरा आ गए। पटेल पत्नी की बीमारी से दुखी थे। परन्तु वल्लभ एक केस लड रहे थे अत उन्होंने लोगो को, जिनका मुकदमा लिया था, भाग्य के भरोसे नही छोडा। उनके मुकदमे के लिए वल्लभ को बराबर बम्बई से गोधरा आना पडता था।

एक दिन जब मुकदमे की सुनवाई हो रही थी तो उन्हे एक तार मिला। तार को पढकर उन्होने चुपचाप उसे अपनी जेब मे रख लिया और मुकदमे की सुनवाई होती रही। अदालत समाप्त होने पर ही उन्होने अपनी पत्नी की मृत्यु के तार के बारे मे अन्य लोगो को पत्नी के तार के बारे मे बताया। पत्नी की मृत्यु के समय वल्लभभाई की आयु 34 वर्ष थी, तब भी उन्होने दूसरे विवाह की नही सोचा।

थोडे दिन गोधरा रहने के बाद वल्लभभाई बोरसद आ गए। यहा पर फौजदारी के मुकदमे अधिक होते थे। यही पर इन्हे मनुष्यो के विचित्र स्वभावो का अच्छा ज्ञान प्राप्त हो गया। ये बाल की खाल निकालने तथा जिरह करने मे बडे-बडो के कान काटने लगे थे। इनकी दलीलो को सुनकर सभी दग रह जाते थे। पुलिस के अफसर भी इनसे घबराते थे। एक अग्रेज मजिस्ट्रेट जिसका नाम हस्बेण्ड था, लोगो को बहुत तग किया करता था। पटेल ने अपनी कानूनी योग्यता से उसको इतना तग किया कि वह सदैव के लिए सुधर गया।

बोरसद मे पटेल की वकालत शीघ्र ही चमक उठी। सबसे अधिक अपराध इसी इलाके मे होते थे। अत सरकार ने इधर के

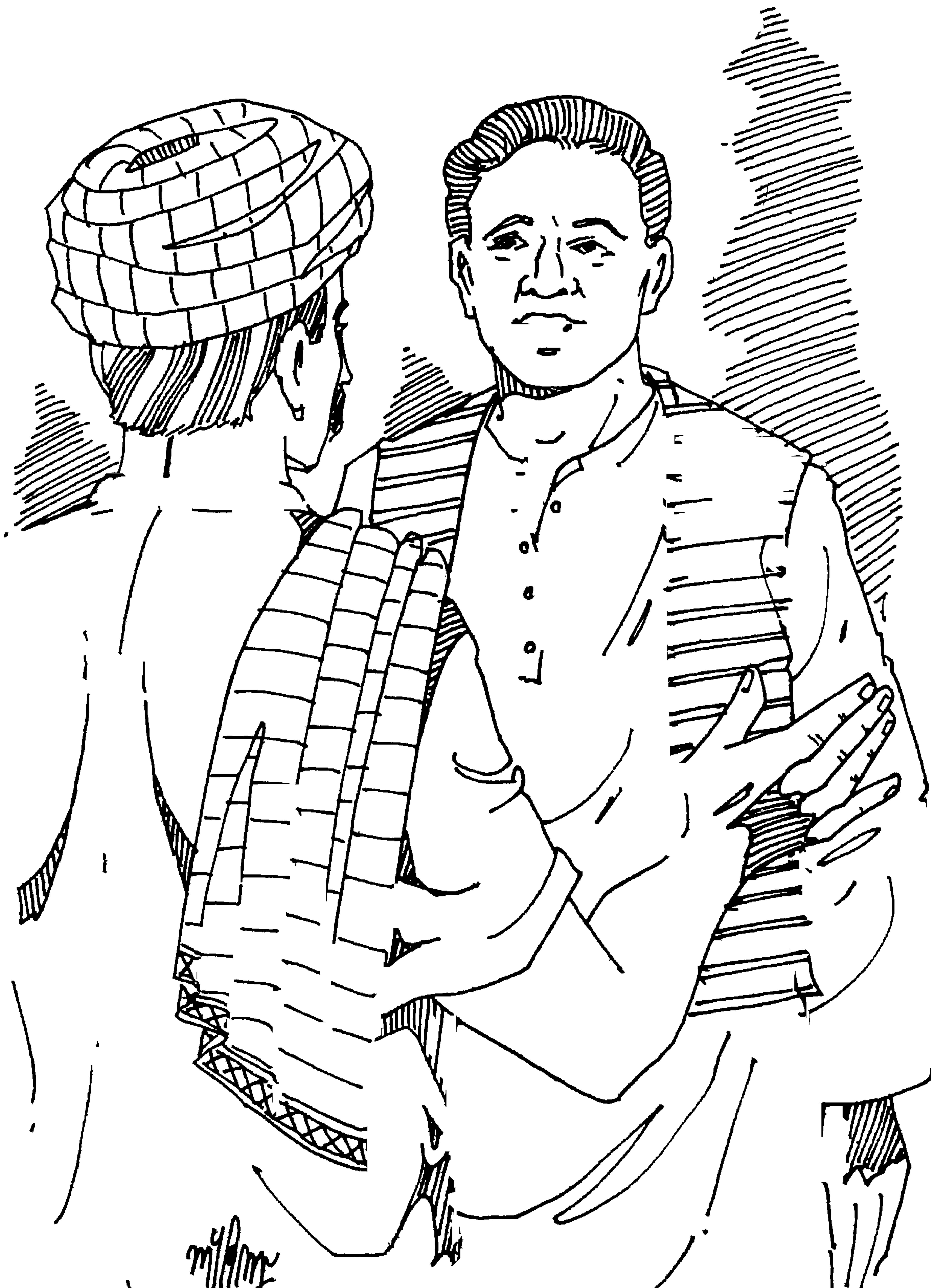

ध्यान चार्ज-शीट की इस बात की ओर दिलाया गया कि चार्ज-शीट मे अपराधी की उम्र 30 वर्ष लिखी हुई है। पहले वाली 9 मास की सजा अभियुक्त के मा के गर्भ मे एकान्तवास की है। अदालत मे बैठे लोग यह सुनकर हस पडे। सरकारी वकील के हाथो के तोते उड गए। वल्लभभाई ने सबकी कडी आलोचना की और अपने भाई के ऊपर की गई आलोचना को भी उसने रद्द करवा दिया और अभियुक्त भी रिहा करवा दिया गया। आलोचना मे सुपरिण्टेण्डेण्ट को भी नही छोड़ा गया और उसे त्याग-पत्र देना पडा।

इसी तरह वल्लभभाई ने कई और दिलचस्प मुकदमो की पैरवी करके लोगो को न्याय दिलाया।

अब वल्लभभाई ने अपनी धाक चारो ओर जमा ली थी। सरदार के पास काफी धन हो गया था। अब उन्हे अपनी आकाक्षापूर्ण होती हुई दिखाई दी। अब वे बैरिस्टरी पास करने के लिए विलायत जाने की सोचने लगे।

विलायत जाने के लिए आपने एक कम्पनी से पत्र-व्यवहार भी किया। कम्पनी का वह पत्र सयोग से बडे भाई के हाथ मे पड गया। पत्र पढकर उनके मन मे भी विलायत जाने की इच्छा उत्पन्न हो गई। इन्होने वल्लभ से कहा, "मै तुम्हारा बडा भाई हू, अत तुम मुझे विलायत जाने दो, जब मै पढ़कर वापस आ जाऊगा तब तुम विलायत चले जाना। यदि मै अब नही गया तो फिर कभी नहीं जा सकूगा।"

वल्लभभाई ने अपने बडे भाई की बात मान ली और इससे एकमत हो गए कि पहले विट्ठलभाई ही विलायत जाए। जब वे वापस पढकर आ जाएंगे तब पटेल विलायत चला जाएगा।

वल्लभभाई ने अपनी भाई की बात ही नही मानी बल्कि उनको विलायत मे खर्च भेजने की ज़िम्मेदारी भी ले ली।

विट्ठलभाई घर मे बिना बताए विलायत चले गए। पटेल जव बोरसद वापस लौटे तभी सबको विट्ठलभाई के जाने का समाचार ज्ञात हुआ।

वल्लभभाई की वकालत इस समय पूरे जोर पर थी। पानी की तरह पैसा आ रहा था। वल्लभभाई को अब कोई चिन्ता नही थी।

विट्ठलभाई लगभग तीन वर्ष तक विलायत मे रहे। पढाई समाप्त करने पर वे वापस आ गए। इन्होने बम्बई मे अपनी वकालत शुरू की और सपरिवार वही रहने लगे।

अव वल्लभभाई ने भी विलायत जाने की तैयारी कर ली। उन्होने अपने विदेश-गमन के बारे मे किसी को भी नही बताया। सभी तैयारी उन्होने पहले ही कर ली थी। अपने बच्चों के पालन-पोषण का भार उन्होंने छोटे भाई को सौप दिया। 10 अगस्त, 1909 को वे लन्दन के लिए रवानी हो गए।

वे यहा पर मिडल-टेम्पल मे पढने लगे। यहा पर इन्होने मिडल-टेम्पल का पुस्तकालय जो इनके घर से 11 मील दूर था, वहा जाकर यह दिनभर पढा करते। दिन मे इन्होने 17-17 घण्टे तक भी पढाई की। भोजन करने का भी इनको ध्यान नही रहता था। वही पर ये अपने लिए दूध-रोटी मगा लिया करते थे। कभी-कभी पढने मे इतने मग्न हो जाते कि इनको पुस्तकालय के बन्द होने के समय का भी ध्यान नही रहता। जब चपरासी आकर इनको बताता कि पुस्तकालय के बन्द होने का समय हो गया है तब कही जाकर ये अपना सामान उठाते थे और पैदल ही अपने निवास-स्थान को रात के समय वापस आते थे। पैदल चलने का इनको प्रतिदिन अभ्यास हो गया था और इससे इनका स्वास्थ्य भी ठीक हो गया था।

परिश्रम का परिणाम यह हुआ कि शीघ्र ही अपने लक्ष्य की ओर तीव्र गति से बढने लगे।

बैरिस्टरी की परीक्षा इन्होंने प्रथम श्रेणी मे उत्तीर्ण की। परीक्षक इनके प्रश्नो के उत्तरो से बहुत प्रभावित हुआ और इनकी बडी प्रशसा की। सरदार को 50 पौण्ड का पुरस्कार मिला और इनकी फीस भी माफ कर दी गई।

इनकी योग्यता को देखकर एक परीक्षक ने इनको कोई ऊचा पद देने की भी सिफारिश की।

भारतवासियो ने भी इनको काफी मान दिया।

इग्लैण्ड मे इन्होने अपना जीवन पूर्ण सादगी से बिताया। वहा इनके रहने का ढग पूर्णतया भारतीय ही रहा। इन्होने अपना समय व्यर्थ नही गवाया। पास होने पर ये दूसरे देशो मे भ्रमण के लिए नही गए। इसके पश्चात् इन्हे दुबारा विदेश जाने का भी अवसर नही मिला।

वल्लभभाई अत्यन्त ही सहनशील व्यक्ति थे। जब ये लन्दन में थे तो एक विद्यार्थी ने इनसे 75 पौण्ड उधार ले लिए थे। जब वल्लभ ने रुपया वापस मागा तो आपस में कहा-सुनी हो गई। विद्यार्थी ने वल्लभ के साथ अशिष्ट व्यवहार किया और वल्लभ से नाराज हो गया और उनसे बोलना तक बन्द कर दिया। वल्लभ जब वापस आ गए तो उस विद्यार्थी ने रुपये वापस भेज दिए और अपने व्यवहार के लिए क्षमा भी मागी।

इसी प्रकार वल्लभ की सहनशक्ति का एक और उदाहरण सामने आया है।

वल्लभभाई जिस मकान मे रहते थे, एक दिन नहाते समय इनका पाच फिसल गया। बाद मे इनको बुखार तथा पैर मे दर्द मालूम हुआ। वल्लभभाई एक नर्सिग होम मे प्रविष्ट हो गए। वहा पर इनको कोई आराम नही हुआ। पैर का दर्द बढ रहा था। नर्सिग होम के डॉक्टरो ने सरदार को पैर कटवाने के लिए कहा परन्तु

वल्लभभाई इसके लिए राजी नही हुए।

वल्लभभाई ने उस सर्जन की चिकित्सा छोड दी और डॉक्टर वी. टी. पटेल नाम के एक प्रोफेसर ने इनकी पूर्णयिता जाच की। इनको दुबारा आपरेशन करवाने की सलाह दी। वल्लभभाई को यह भी कहा कि बिना बेहोशी की दवा लिए आपरेशन करवाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वल्लभभाई ने उनकी बात मान ली और बिना बेहोश हुए ही आपरेशन करवा लिया। वल्लभभाई की सहनशक्ति को देखकर डॉक्टर भी दंग रह गया।

वल्लभभाई विलायत से 23 फरवरी, 1913 को बम्बई पहुचे। इन्होने बम्बई मे अपनी वकालत शुरू नही की। ये अहमदाबाद आए और यहा पर इन्होने अपनी वकालत आरम्भ कर दी। थोडे ही दिनो मे पटेल बहुत विख्यात हो गए और अहमदाबाद के बडे बैरिस्टरो मे गिने जाने लगे। बडे-बडे मुकदमो मे अपने पैरवी की और अपने अभियुक्तो को बरी करा दिया। लक्ष्मी की वर्षा होने लगी।

अब पटेल पर पश्चिमी सभ्यता का रग जमने लगा। अपने ऑफिस को पटेल ने नया रूप दिया और पश्चिमी फर्नीचर से उसे सजाया। पटेल अब ठाठ से रहने लगे।

वल्लभभाई पटेल ने अपनी फीस अहमदाबाद के बैरिस्टरो से अधिक रखी। पटेल अदालत के काम के बाद क्लब भी जाने लगे। क्लब का नाम था गुजरात क्लब। यहा पर ये चमनलाल बैरिस्टर के साथ ब्रिज खेला करते। ब्रिज खेलने मे भी ये बडे होशियार हो गए। श्री वाडिया तथा ब्रोमर नाम के वकीलो के साथ श्री चमनलाल तथा पटेल का ब्रिज मे मुकाबला भी हुआ। पटेल तथा चमनलाल ने अपने-अपने विरोधियो को बुरी तरह पराजित कर दिया।

अब इस नवयुवक का व्यक्तित्व निखर आया। इसकी ओर

नए नवयुवक आकर्षित होने लगे। कुछ लोग इनकी आलोचना भी करने लगे।

बम्बई मे जब विट्ठलभाई के पास धन हो गया तो उन्होने अपना ध्यान लोकसेवा की ओर भी दिया। दोनो भाइयो ने मिलकर यह निर्णय किया कि बडे भाई देश-सेवा करे और छोटे भाई परिवार के सदस्यो का पालन-पोषण करेगा।

विट्ठलभाई राजनैतिक क्षेत्र मे भी काफी प्रसिद्ध हुए। सन् 1919 मे लेजिस्लेटिव एसेम्बली के लोअर हाउस प्रधान चुने गए। विट्ठलभाई ने अपनी योग्यता से पद का मान बढा दिया। विदेशी भी इनके कार्य करने की योग्यता की प्रशसा करने से नही चूकते थे।

गांधी जी से भेंट

कुछ दिन पूर्व ही महात्मा गाधी अहमदाबाद आकर रहने लगे। वे अभी अफ्रीका के आन्दोलन मे सफलता प्राप्त करके लौटे थे। पटेल की भेट गाधी जी से एक क्लब में हुई।

गाधी जी अहिसावादी थे। वे अहिसा द्वारा ही भारत को स्वतन्त्र कराना चाहते थे और जनता मे भी अहिसा का प्रचार करते थे। जनता हैरान थी कि अहिसा के बल पर विदेशी सत्ता से भला कैसे टक्कर ली जा सकती है! कई लोग गाधी जी का मजाक उड़ाने लगे और गाधी जी के विचारों पर हसने लगे।

आरम्भ मे सरदार पटेल पर भी गाधी जी के शब्दो का कोई असर नही हुआ क्योंकि पटेल को राजनैतिक जीवन मे कुछ सरोकार नहीं था।

अहमदाबाद मे सन्ध्या से समय वकील क्लब मे इकट्ठे होते थे और वही पर गाधी जी के बारे में भी चर्चा होती थी। वे सब

मिलकर गांधी जी से असहमति जताते थे।

एक दिन गांधी जी ने क्लब के सदस्यों के सामने अपना भाषण दिया। जब गांधी जी भाषण दे रहे थे तो पटेल एक कोने मे ताश खेलते हुए हस रहे थे।

गांधी जी के शब्दों मे जादू था जो लोगों को चुम्बक की तरह अपनी ओर खींच लेता था। धीरे-धीरे पटेल भी इनकी ओर खिचने लगे और गांधी जी के दृढ विश्वास की प्रशसा करने लगे। गांधी जी ने अपने विचारो द्वारा गुजरात के राजनैतिक जीवन मे नया प्राण डाल दिया।

पटेल ने अपना राजनैतिक जीवन गोधरा से आरम्भ किया। सबसे पहले पटेल और गांधी जी का यही साथ हुआ।

इस समय गुजरात मे बेगार प्रथा जोरो पर थी।

इस प्रथा को हटाने के लिए एक सम्मेलन हुआ जो गोधरा कांफ्रेंस के नाम से प्रसिद्ध है। इसके सभापति गांधी जी थे। बेगार प्रथा को हटाने के लिए तथा सम्मेलन के प्रस्तावो को कार्यान्वित करने के लिए एक कमेटी का भी गठन हुआ जिसका मन्त्री-पद पटेल को सौंपा गया। मन्त्री-पद पर रहते हुए पटेल ने अपनी जिम्मेदारी को समझा और उसको पूरी योग्यता से पूरा भी किया।

पटेल ने सबसे पहले बेगार की प्रथा को मिटाने का प्रण किया। पटेल ने कमिश्नर को एक पत्र लिखा जो सरकार के नाम एक नोटिस था। पत्र मे सात दिन के भीतर ही बेगार प्रथा को बन्द करने के लिए कहा था और साथ मे यह भी लिखा कि यदि 7 दिन के अन्दर बेगार प्रथा को समाप्त नही किया गया तो बेगार प्रथा को हाईकोर्ट के फैसले के आधार पर गैर-कानूनी घोषित करा दिया जाएगा।

वल्लभभाई पटेल ने इस बारे मे दो और यादी पत्र लिखे।

कमिश्नर ने पटेल को बातचीत के लिए बुलाया और उसके कहने के अनुसार बेगार की समाप्ति की घोषणा कर दी।

गाधी जी ने जब यह समाचार सुना तो वे बहुत खुश हुए।

गाधी जी इस समय चम्पारन मे थे। वहा नील का व्यवसाय अग्रजो के हाथ मे था। अंग्रेज किसानो को बहुत परेशान करते थे। गाधी जी ने उनका दु ख दूर करने मे पूरी सहायता की।

अब गाधी जी ने गुजरात मे अपने विचारो को कार्य रूप मे परिवर्तित करने के लिए एक योजना बनाई। पटेल को यह योजना बहुत पसन्द आई। गाधी जी को पटेल का साथ बडा अच्छा लगा। अच्छा लगता क्यो न, उन्हे एक योग्य विश्वस्त साथी जो मिल गया था। गाधी जी के साथ रहने पर पटेल की विचार-दशा बदल गई।

पटेल 1916 ई० मे गाधी जी के साथ पूरी तरह मिल गए। पटेल ने अपनी वकालत छोड दी। गाधी जी के साथ वे एक मित्र के रूप मे रहने लगे। वहा महात्मा गाधी ने जितने भी आन्दोलन किए, पटेल ने सबमे गाधी जी का साथ दिया। इस तरह वह महात्मा गाधी के दाहिने हाथ बन गए।

खेड़ा सत्याग्रह

सन् 1917 मे वर्षा ऋतु मे फसले खराब हो गई। खेड़ा जिले मे अकाल जैसे स्थिति हो गई। किसानो मे इतनी शक्ति नहीं थी कि वे लगान दे सकें। फसल खराब हो जाने पर वहा के किसानो ने सरकार से लगान माफ के लिए प्रार्थना की। बेचारे किसानो की पुकार की ओर किसी ने भी ध्यान नही दिया। सरकार चाहती थी कि किसानो से लगान जबर्दस्ती प्राप्त कर लिया जाए।

किसान दुविधा मे थे कि ऐसे समय मे लगान कहा से दे। पशुओं को चारा भी नही प्राप्त हो रहा था। गरीब लोगो के भूखे मरने की स्थिति उत्पन्न हो गई थी।

इस पर गाधी जी ने खेडा मे लगान न देने का आन्दोलन आरम्भ कर दिया। उधर चम्पारन मे भी गाधी जी ने अग्रेज जमीदारो के विरुद्ध मोर्चा खोल रखा था। अत गाधी जी के लिए यहा रहना उचित नही था। उन्होने इस सत्याग्रह का भार पटेल को सौप दिया। पटेल ने इसको स्वीकार भी कर लिया। गाधी जी को पटेल पर जिम्मेवारी सौपते हुए अति प्रसन्नता हुई। उन्हे पूर्ण विश्वास था कि पटेल अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह निभाएगा और सफलता भी उसकी होगी।

पटेल ने अब विदेशी पहनावा उतार कर स्वदेशी पहनावा पहन लिया और गाव-गाव घूमना आरम्भ कर दिया। इन्होने किसानो मे नवजागरण पैदा किया। किसानो को लगान न देने के लिए उभारा। थोडे ही दिनो मे जिले के सारे किसान सरकार को लगान न देने के लिए तैयार हो गए।

धीरे-धीरे आन्दोनल जोर पकडने लगा। सरकार की आखे भी खुली। आन्दोलन की उग्रता देख सरकार ने 25 अप्रैल, 1918 को किसानो की माग स्वीकार कर ली और कुछ किसानो का लगान माफ कर दिया। इससे किसानो को खुशी नही हुई। पटेल ने किसानो का नेतृत्व करते हुए उन्हे प्रेरित किया। नए जोश के साथ आन्दोलन और तीव्र हुआ। अन्त मे जून के अन्तिम सप्ताह मे अग्रेज अधिकारी ने लगान माफी की घोषणा कर दी। वल्लभभाई पटेल को क्षेत्र की जनता ने हाथो मे उठा लिया। भारत के इतिहास मे यह आन्दोलन एक मील का पत्थर था। लोगो को गाधी के अहिसा आन्दोलन पर विश्वास बढा। इस सफलता पर गाधी जी ने

पटेल की प्रशसा की और उन्हे इस आन्दोलन का सरदार बताया। अब वल्लभभाई पटेल सरदार पटेल कहलाने लगे।

काला कानून

1918 मे जर्मनी और इग्लैण्ड मे युद्ध छिड गया। जिसे प्रथम विश्व-युद्ध कहते है। इस बडी लडाई मे गाधी जी तथा अन्य नेताओ ने सरकार की बहुत सहायता की। गाधी जी ने गाव-गाव घूमकर जनता को सेना में भर्ती कराने मे पूरा सहयोग दिया और सरकार को चन्दा भी इकट्ठा करके दिया। सभी ने तन-मन और धन से विदेशी सत्ता की सहायता की ताकि अग्रेज भारतीयो को कुछ और अधिकार दे। अग्रेजो की जीत हुई। नेताओं को आशा थी कि विदेशी सरकार खुश होकर देश का कुछ भला करेगी, परन्तु अपना उल्लू सीधा करने वाली कहावत पूरी तरह चरितार्थ हुई। युद्ध जीतने के पश्चात् अग्रेजो ने भी आखे बदल ली।

भारत की सहायता के बदले विदेशी सरकार ने रोलट एक्ट पास कर दिया। इस एक्ट का दूसरा नाम काला कानून था। इस कानून के पास हो जाने से पुलिस के अधिकारो की बढोत्तरी हो गई। पुलिस को यह अधिकार मिल गया कि वह किसी भी व्यक्ति पर शक हो जाने पर उसको पकड सकती थी। इन लोगो के मुकदमे का फैसला बिना किसी वकील के तथा बिना कोई सफाई लिए हुए किया जा सकता था।

सारे भारत मे काले कानून का विरोध हुआ। प० मदनमोहन मालवीय दिल्ली की बडी सभाओ में इस कानून का विरोध कर रहे थे, पर सरकार ने काला कानून पास कर ही दिया।

काले कानून को बनाने वाली सरकार को हटाने के लिए

महात्मा गाधी ने 23 मार्च, 1919 ई. को जनता को 24 घण्टे का उपवास करने के लिए कहा। 6 अप्रैल को भूखे रहकर प्रार्थना करने का भी लोगो से आह्वान किया।

इस अवसर पर सरदार पटेल के नेतृत्व मे अहमदाबाद मे विशाल जलसा निकाला गया।

गलती से 30 मार्च को दिल्ली मे हडताल हो गई। हडतालियो तथा दुकानदारो मे कुछ झगडा भी हो गया तथा हिन्दू-मुस्लिम दगा हो गया। सेना ने गोली चला दी, फलस्वरूप कुछ आदमी मर गए। 6 अप्रैल को सम्पूर्ण भारत मे काले कानून के विरुद्ध हडताल हो गई।

दिल्ली की जनता मे क्रोध की भावनाए उत्पन्न हो गई थी। वे प्रतिशोध लेने पर उतर आए थे। गाधी जी उनको शान्त करने के लिए दिल्ली जा रहे थे। 10 अप्रैल को सरकार ने गाधी जी को दिल्ली पहुचने से पहले ही हिरासत मे ले लिया और वे दिल्ली न पहुच सके। सरकार के इस व्यवहार से पजाबवासी भी उत्तेजित हो गए। पजाब के दो बडे नेताओ को भी पकड़ लिया गया और उनको पजाब के बाहर भेज दिया गया। यह सब देखकर अमृतसर का एक शान्ति दल डिप्टी कमिश्नर से मिलने उनके बंगले की ओर गया। यह शान्ति दल अपने दोनो नेताओ की प्रार्थना करके छुडाना चाहता था। रास्ते मे इस दल को रोका गया और इस निहत्थे शान्ति दल पर गोली भी चलाई गई। इससे जनता ने और उग्र रूप धारण कर लिया। उसे रास्ते मे जो भी अग्रेज मिला उसे खूब मारा।

अमृतसर मे मार्शल लॉ लागू हो गया। नगर का प्रबन्ध जनरल डायर के हाथो मे दे दिया गया। जनरल डायर ने नगर मे सभा करने पर रोक लगा दी। इसके विरोध मे 13 अप्रैल को जलियावाला बाग मे सभा हुई। सभा मे बडी भीड थी। सभा जिस समय पूर्ण

(१३२६८)

विकसित थी तो जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया। 14 मिनट तक गोली चली। बाग के चारो ओर पुलिस का पहरा था। बाग मे जाने का एक ही मार्ग था। इस कारण कोई भी भाग नही सकता था। बाग मे बहुत भीड थी। बहुत-से बूढे, बच्चे, स्त्रिया तथा नवयुवक मरे और घायल हो गए। वहा एक कुआ है जो अगले दिन लाशो से पटा मिला।

लाहौर, अमृतसर, कसूर आदि स्थानो पर सेना ने शासन सम्भाल लिया। जनता तथा स्त्रियो की असमत लूट ली गई। लोगो को नगा करके पीटा गया। ऐसे निर्दयी अधिकारी को सरकार ने क्षमा कर दिया और वापस विलायत भेज दिया। कई वर्ष बाद ऊधमसिह ने विलायत जाकर डायर को गोली से भून दिया और जलियावाला बाग हत्याकाण्ड का बदला लिया।

असहयोग आन्दोलन

इन दोनो घटनाओ से जनता मे रोष की भावना उत्पन्न हो गई। अब स्वतन्त्रता की लहर देश के कोने-कोने मे उठने लगी। गाधी जी को भी इन घटनाओ से गहरा आघात पहुचा। उन्होने 1920 मे कलकत्ता के अधिवेशन मे अहिसात्मक असहयोग का निश्चय किया। कौसिलो, स्कूलो और अदालतो के बहिष्कार के बारे मे प्रस्ताव पास हुए। इसके जवाब मे असख्य विद्यार्थियो ने स्कूलो तथा कॉलेजो में जाना बन्द कर दिया। वकीलो ने वकालत छोड दी। सरकारी कर्मचारियो ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिए।

असहयोग आन्दोलन आरम्भ होते ही महात्मा गाधी ने 'कैसरे हिन्द' का तमगा वायसराय को वापस कर दिया। पटेल, प. मोतीलाल, प. जवाहरलाल आदि ने देश मे घूम-घूमकर सरकार से

सहयोग करने का प्रचार प्रारम्भ किया।

सरदार पटेल ने भी अपनी बेरिस्टरी छोड दी थी और अपनी सारी शक्ति देश-सेवा मे लगाने का उन्होंने प्रण कर लिया। उन्होंने गुजरात का दौरा किया। वहा पर भाषण किए। जनता को उत्साहित किया। गुजरात के घर-घर मे इनकी पूजा होने लगी।

पजाब की घटना से इनके मन मे अग्रेजो के प्रति इतनी घृणा उत्पन्न हो गई कि उन्होने अपने बच्चो को अग्रेजी स्कूलो से हटा लिया। पहले यह अपने बच्चो को पढने के लिए विलायत भेजना चाहते थे, किन्तु अब इनके विचारो मे क्रान्तिकारी परितर्वन आ गया। आपने गुजरात विद्यापीठ की स्थापना की जिसके लिए इन्होने वर्मा तक जाकर चन्दा जमा किया और दस लाख रुपये जमा कर लिए।

सन् 1922 ई॰ की पाच फरवरी को गोरखपुर के समीप के स्टेशन चौरी-चौरा में पुलिस और जनता मे सघर्ष हो गया। जनता ने उग्र रूप धारण कर लिया और वहा के लोगों ने सब सिपाहियो तथा थानेदार को थाने मे बन्द करके जला दिया। असहयोग आन्दोलन के लिए शान्ति की आवश्यकता थी परन्तु यहा की जनता शान्ति बनाए रखने मे असफल रही। इस कारण महात्मा गाधी ने आन्दोलन कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया। सरकार ने गाधी जी पर मुकदमा चलाकर उनको 6 वर्ष कैद की सजा सुना दी।

महात्मा जी के पकडे जाने पर गुजरात मे आन्दोलन का कार्यभार सरदार पटेल ने ही सम्भाला।

बोरसद की जनता को भी सराकर ने दबाया। वहा की जनता पर सरकार ने कई जुर्म लगाकर वहा पुलिस-व्यवस्था बढाने के लिए जनता पर चालीस हजार रुपये कर लगा दिए। जो जुर्म वहा की

जनता पर लगाए गए थ, उनमे तनिक भी सत्यता नहीं थी। यह वात सरदार से भी छिपी हुई नही थी। सरदार ने यहा पर भी इसका विरोध किया और सरकार के विरुद्ध एक बड़ा भारी जनमत खडा कर दिया। अन्त मे सरकार तथा वहा के पुलिस अफसरो को इस शेर के सामने घुटने टेकने पडे।

1923 मे नागपुर मे कांग्रेस ने अपने तिरगे झण्डे के साथ जुलूस निकालने की घोषणा की। अग्रेज सरकार ने इस जुलूस पर प्रतिबन्ध लगा दिया। सरदार पटेल ने यहा पर अपनी योग्यता का अपूर्व परिचय दिया। उन्होने गुजरात से कई जत्थे स्वय सेवको के भेजे। कांग्रेज ने जुलूस पर लगाए गए प्रतिबन्ध को अपना अपमान समझा। इसी समय सेठ जमनीलाल को सरकार ने हिरासत मे ले लिया और अव इस सत्याग्रह का कार्यभार पटेल के कधो पर ही आ गया। उन्होने आन्दोलन को नया ही रूप दिया जिससे सारे भारतवर्ष मे आन्दोलन हो गया। सगठन की प्रवलता को देखकर सरकार इनके आगे झुक गई। गवर्नर ने सरदार पटेल से बातचीत करने के पश्चात् जुलूस निकालने की आज्ञा दे दी और जनता की मागे भी स्वीकार कर ली गई।

महात्मा गाधी जेल से छूट गए। सरदार को अब कुछ आराम मिला। गाधी जी के जेल जाने पर पटेल की जिम्मेदारी बहुत बढ गई थी। गाधी जी ने पटेल को अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह निभाने पर हार्दिक वधाई दी।

इसी समय आप अहमदाबाद म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन भी वन गए। आपने इस पद पर रहते हुए लगातार पांच वर्ष तक जनता की निरन्तर सेवा की और वही कार्य किए जिनसे जनता की अधिक भलाई होती थी।

गुजरात मे वडे जोर की वाढ आई जिससे अनेक गाव वरवाद

हो गए। ऐसे समय पटेल ने बाढ-पीड़ितो की बहुत सहायता की थी।

बारडोली का सत्याग्रह

गुजरात प्रान्त मे बारडोली एक छोटा-सा तालुका है। यहा पर 20 या 30 वर्ष बाद भूमि का नया बन्दोबस्त होता था और सरकार की ओर से लगान भी तय कर दिया जाता था। जो लगान सरकार द्वारा तय कर दिया जाता था, किसानो को अगले वर्षो मे वह देना पडता था।

सदैव की भाति अधिकारियो ने भूमि की जाच-पड़ताल की और लगान मे 25 प्रतिशत वृद्धि कर देने का सुझाव भी सरकार को दिया गया। जनता बाढ व अकाल के कारण आक्रान्त थी तथा किसानो की दशा मे तनिक भी सुधार नही था। किसान जो लगान अब भी सरकार को दे रहे थे वह भी अनुचित था। सरकारी अधिकारियो की गलत रिपोर्ट के कारण जुलाई, सन् 1927 ई० को सरकार ने लगान की दर मे 25 प्रतिशत की वृद्धि कर दी।

सरकार ने लगान इसलिए बढ़ा दिया कि भूमि की उपज बढ गई थी और खेतो का मूल्य भी बढ़ गया था।

बारडोली तालुका समिति ने सरकारी अधिकारियो की रिपोर्ट का खण्डन किया और आकड़े देकर सरकार को बताया कि लगान मे वृद्धि उचित नही है और सरकार की लगान की मौजूदा दर को भी ज्यादा बताया। जनता के प्रतिनिधि सरकार से भी मिले परन्तु अधिकारियो ने इनकी प्रार्थना अस्वीकार कर दी।

सरकार ने लगान वृद्धि का प्रस्ताव पास कर दिया। इसके बाद राव साहब दादूभाई देसाई की अध्यक्षता मे किसानो की एक सभा

हुई और इस सभा मे लगान की बढी हुई दर न चुकाने का फैसला किया गया। सरकार पर इसका असर नही पडा और अधिकारीगणो को बढी हुई दरो पर लगान वसूल करने के लिए सरकारी आदेश आ गए।

अब सब लोग पटेल के पास आए। सरदार ने उनकी बात ध्यान से सुनी। पटेल ने किसानो को समझाया और आशा भी दिलाई। सरकार ने उनसे कहा, "आप सब लोग एक होकर लगान न देने का फैसला कर लो। हर तरह का कष्ट सहन करने के लिए तैयार हो जाओ। यदि आप यह सब कुछ कर सके तो मै आपकी सहायता करने के लिए तैयार हू। तुम लोग सारे तालुके मे घूमो और मुझे आकर बताओ कि दूसरे किसानो की क्या राय है? क्या वे आपका साथ देने को तैयार है?"

सभी ने पटेल की बात मान ली और कार्यकर्ता रात-दिन एक करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमने लगे। आठ-दस दिन मे ही उन्होने सारे तालुके की छान-बीन कर ली। अधिकाश गावो की राय जानकर सभी लोग अहमदाबाद लौटे। इनके साथ जब पड्यजी, रविशकर महाराज आदि भी थे। पटेल के नेतृत्व मे यह मण्डली गाधी जी से जाकर मिली। गाधी जी को पूर्ण स्थिति से अवगत कराया गया। गाधी जी ने पटेल को विजयी होने का आशीर्वाद दिया।

पटेल 12 फरवरी को बारडोली आए। उस दिन तालुके के सभी गावो के लोग वहा एकत्रित हुए। सरदार ने सबकी अच्छी तरह परीक्षा की और उन्हे कसौटी पर भी कसा। पटेल ने जनता का आह्वान किया। किसानो को आश्वासन देकर पटेल अहमदाबाद वापस आ गए। 16 फरवरी को सरदार ने सरकार को पत्र लिखा जिसमे प्रार्थना की गई कि सरकार इस समय लगान की वसूली

स्थगित कर दे और सारे मामले पर नए सिरे से विचार करे जिससे किसानों को भी कुछ राहत मिल सके।

गर्वनर ने इस पत्र पर विशेष ध्यान नही दिया। पत्र को माल विभाग मे जाच के लिए भेज दिया गया। लगान वसूली का आदेश नही रुका। अधिकारी लगान वसूली के लिए कार्यवाही करने लगे।

सरकार ने 12 फरवरी तक किसानो को कर चुकाने के लिए मुनादी कर दी थी। मालगुजारी के लिए जो अधिकारी नियुक्त हुए थे वे तरह-तरह के उपाय काम मे लाते थे परन्तु वे किसानों से कर वसूल करने मे असफल रहे।

जब 12 फरवरी तक खजाने मे कुछ भी जमा नही हुआ तो सरकार का क्रोध बढ गया। सरकार ने कर वसूल करने वालो को अयोग्य समझकर उनको निकालकर उनके स्थान पर नए अधिकारी नियुक्त किए। ये अफसर ऐसे थे जो किसानो के साथ कड़ाई भी कर सकते थे।

किसान सगठन अब सुदृढ हो गया था। आन्दोलन का सब समाचार 'सत्याग्रह समाचार' नाम दैनिक समाचार-पत्र मे छपता था। अधिकारियो को किसानो ने स्पष्ट बता दिया कि वे कर नही देगे।

सरकारी अधिकारी जब कर वसूल करने आते तो किसान उनका स्वागत नही करते थे। उनसे कोई बात भी नही करता था और न ही उन्हे बैठने के लिए कोई स्थान दिया जाता था। यहा तक कि किसानो ने उनको पानी तक के लिए नही पूछा।

सरकारी अधिकारी किसानो का सामान कुडक कर नीलामी करने लगे, जब किसी भी गाव वाले ने बोली नही बोली।

अधिकारी भी असमजस मे पड गए। अफसर लोग बाहर से

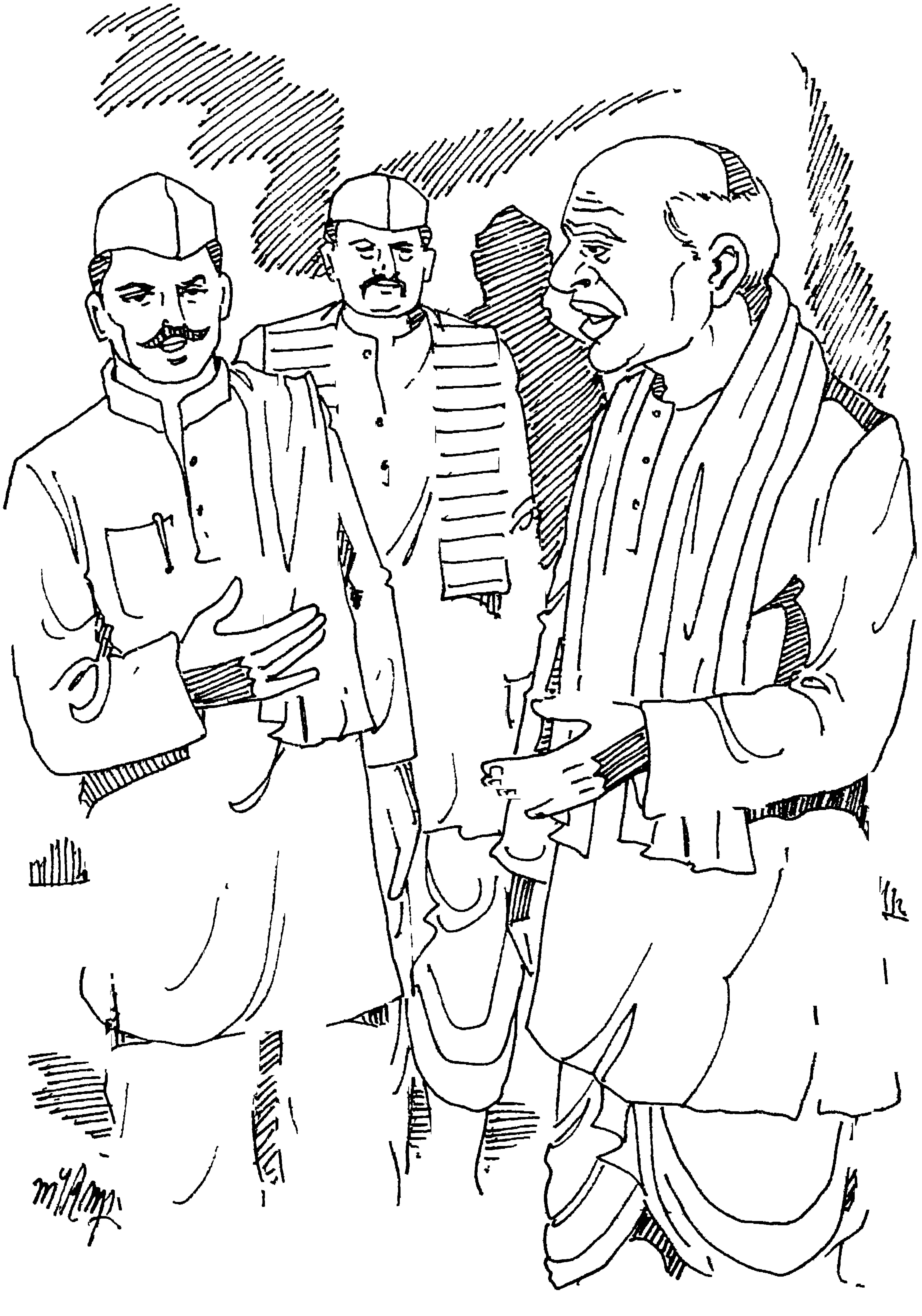

ऐसे लोगो को बुला लाए जो निलामी का सामान खरीदना चाहते थे। नीलामी के सामान की बोली बोलने वालो मे एक पारसी सेठ था। सामान खरीदने के लिए वह बोली तो बोल देता था परन्तु खरीदे हुए सामान को ले जाने के लिए मजदूर भी नही मिलते थे।

पटेल जिले-भर के नेता माने जाते थे। सत्याग्रह का सचालन भी उन्ही के हाथो हो रहा था। वह अपने कार्यो मे किसी को दखल नही देने देते थे, चाहे वह कांग्रेसी ही क्यो न हो।

कुछ बाहरी कांग्रेसी पटेल से मिलने गए। वे बारडोली के आन्दोलन मे सहायता देना चाहते थे। सरदार को उनकी बात पर गुस्सा आया। वे बाहरी सहायता लेना नही चाहते थे। उन्हे बाहरी सहायता की कोई आवश्यकता भी नही थी। उन कांग्रेसजनो ने पटेल को बताया कि वे पारसी सेठ को नीलामी का सामान न खरीदने के लिए मना करने आए है। यह बात सुनकर पटेल ने कहा, "बारडोली मे एक ही नेता है जिसकी आज्ञा सभी मानते है वह है सरदार पटेल।"

कांग्रेसजनो ने गाधी जी से जाकर यह बात कही। गाधी जी इस बात को सुनकर हस पडे और कहने लगे कि वल्लभभाई वास्तव मे सरदार ही है।

अब सरकार को क्रोध और भडक गया था। सेना का भी प्रयोग हुआ। हजारो आदमी हिरासत मे ले लिए गए। पुलिस के अत्याचार बढ गए। घर से स्त्रियो का निकलना कठिन हो गया। पानी पर भी प्रतिबन्ध लग गया। किसानो ने तनिक भी आवाज नही उठाई। वे सब कुछ चुपचाप सहन कर रहे थे।

सरकार ने अब पठानो को भी भर्ती कर लिया। पठान किसानो पर मनमाने अत्याचार करने लगे। सरकार के सभी प्रयत्न विफल हो

गए और वह किसानो को किसी तरह भी नही झुका सकी।

समाचार-पत्रो मे सरकार की निन्दा होने लगी। जनता जब समाचार-पत्र पढती तो उसके हृदयो को ठेस पहुचती थी।

यह सब देखकर बम्बई की कौसिल के 16 सदस्यो ने गर्वनर को अपना त्याग-पत्र दे दिया [उन दिनो गुजरात देशी रियासतो को छोड, बम्बई (आधुनिक महाराष्ट्र) का भाग था।] इसी समय पटेल के बडे भाई दिल्ली मे केन्द्रीय असेम्बली के सभापति थे। उन्होने सरकार से इस मामले मे हस्तक्षेप करने को कहा। सरकार को उन्होने यह धमकी भी दी कि यदि उसकी बात पर विचार न हुआ तो वे अपने पद से त्याग-पत्र दे देंगे और सरदार पटेल के साथ सत्याग्रह मे सम्मिलित होकर देश-सेवा मे हाथ बटाएगे।

देशभर के स्वयसेवक सत्याग्रह को सहायता देने के लिए धन तथा अन्य सामान जुटा रहे थे। प्रत्येक प्रान्त से स्वयंसेवक आने को तैयार थे।

अन्त मे जब सरकारी दमन का कुछ वश न चला तो सरकार को झुकना पडा। एक जांच कमेटी नियुक्त की गई। इसके अध्यक्ष हाईकोर्ट के एक जज थे।

बड़ी दौड़-धूप के बाद सरकार तथा किसानो मे अगस्त, सन् 1928 को समझौता हो गया। अदालत ने केवल साढे छ· प्रतिशत वृद्धि का सुझाव दिया। दोनो पार्टियों ने इसको स्वीकार कर लिया। किसानो की नीलाम की हुई सम्पत्ति किसानो को वापस कर दी गई। लोगो को पुन नौकरियो पर रख लिया गया। गिरफ्तार व्यक्तियो को रिहा कर दिया गया। अगस्त को तालुके-भर मे विजय-दिवस मनाया गया और इस सत्याग्रह के ऐतिहासिक महत्त्व प्राप्त किया।

सरदार को सफलताओ मे से यह सफलता सबसे बडी थी।

पटेल का नाम अब भारत मे ही नही, विदेशो मे भी चमकने लगा।

सरदार पटेल और राष्ट्रीय आन्दोलन

दिसम्बर, 1928 मे पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता मे कलकत्ता मे कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन मे सबसे अधिक चर्चा सरदार पटेल की थी। परन्तु वे अपनी प्रशसा से रोमांचित होने की बजाए पीछे अपने साथियो के बीच श्रोता की तरह बैठे थे।

जैसे ही बारडोली के सत्याग्रहियो को बधाई देने का प्रस्ताव आया, सबने पटेल के दर्शन की माग की। बड़ी मुश्किल से पटेल अपने परिचय के लिए हाथ जोडकर अपने स्थान पर खडे हुए, परन्तु देश-भर से आए प्रतिनिधियो को इतने से सन्तोष नही हुआ। उन्होने माग की कि पटेल मच पर आकर भाषण दे। पटेल सकोच कर रहे थे। उत्साही साथियो ने उन्हे अपने हाथो मे उठा लिया और बलात् मच पर खडा कर दिया। सरदार वल्लभभाई पटेल के मच पर खडे होते ही उनके सम्मान मे जोरदार तालिया बजी, फिर फूल-मालाओ के साथ उनका स्वागत किया गया।

अब पटेल एक राष्ट्रीय नेता के रूप मे सबके समक्ष उपस्थित थे। अपने भाषण मे उन्होने सत्याग्रह का श्रेय स्वयं लेने से साफ इन्कार कर दिया। इस कर्मवीर की विनम्रता और महानता ने सभी कांग्रेसी प्रतिनिधियो का मन मोह लिया और उसी दिन से सरदार वल्लभभाई पटेल गाधी जी के साथ कांग्रेस के शीर्ष नेता गिने जाने लगे।

अधिवेशन मे कांग्रेस ने सरकार को चेतावनी दे डाली कि यदि नेहरू रिपोर्ट पर उसने पूरा-पूरा अमल नही किया तो कांग्रेस अपना ध्येयपूर्ण स्वाधीनता लेना बना लेगी।

इसके बाद पूरा वर्ष बीत गया, परन्तु सरकार टस-से-मस न हुई। दिसम्बर, 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन लाहौर में हुआ तो नेहरू जी ने भारतीयों की उपेक्षा करते जाने के लिए सरकार को आड़े हाथों लिया और घोषणा कर दी कि अब कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करना है। पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हो गया।

2 जनवरी, 1930 को कांग्रेस कार्यसमिति ने फैसला लिया कि प्रतिवर्ष 26 जनवरी का दिन स्वाधीनता-दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस उपलक्ष में स्वाधीन भारत में 26 जनवरी गणतन्त्र दिवस बना।

कार्यसमिति ने साबरमती आश्रम जाकर सविनय अवज्ञा आन्दोलन करने सम्बन्धी सारे अधिकार महात्मा गांधी को सौंप दिए। महात्मा गांधी ने 11 शर्तों वाला एक प्रस्ताव वायसराय के पास भेज दिया। परन्तु वायसराय ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया। अतः आन्दोलन आरम्भ करने का फैसला ले लिया गया यह तय किया गया कि 12 मार्च को महात्मा गांधी साबरमती से सूरत जिले के दांडी नामक स्थान की ओर कूच करेंगे और 6 अप्रैल को दांडी पहुंचकर समुद्र तट पर नमक कानून भंगकर आन्दोलन आरम्भ कर देंगे।

सरदार पटेल ने गांधी जी के दांडी पहुंचने से पहले वहां का वातावरण अनुकूल बनाने का दायित्व अपने कन्धों पर लिया और वे मार्च, 1930 के आरम्भ में ही बोरसद ताल्लुक के गांवों में जा पहुंचे। वहां उन्होंने जनता के बीच सम्पर्क कर उसे आन्दोलन के लिए तैयार करना आरम्भ कर दिया। जनता ने अपने बीच अपने लोकप्रिय नेता को देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। पटेल

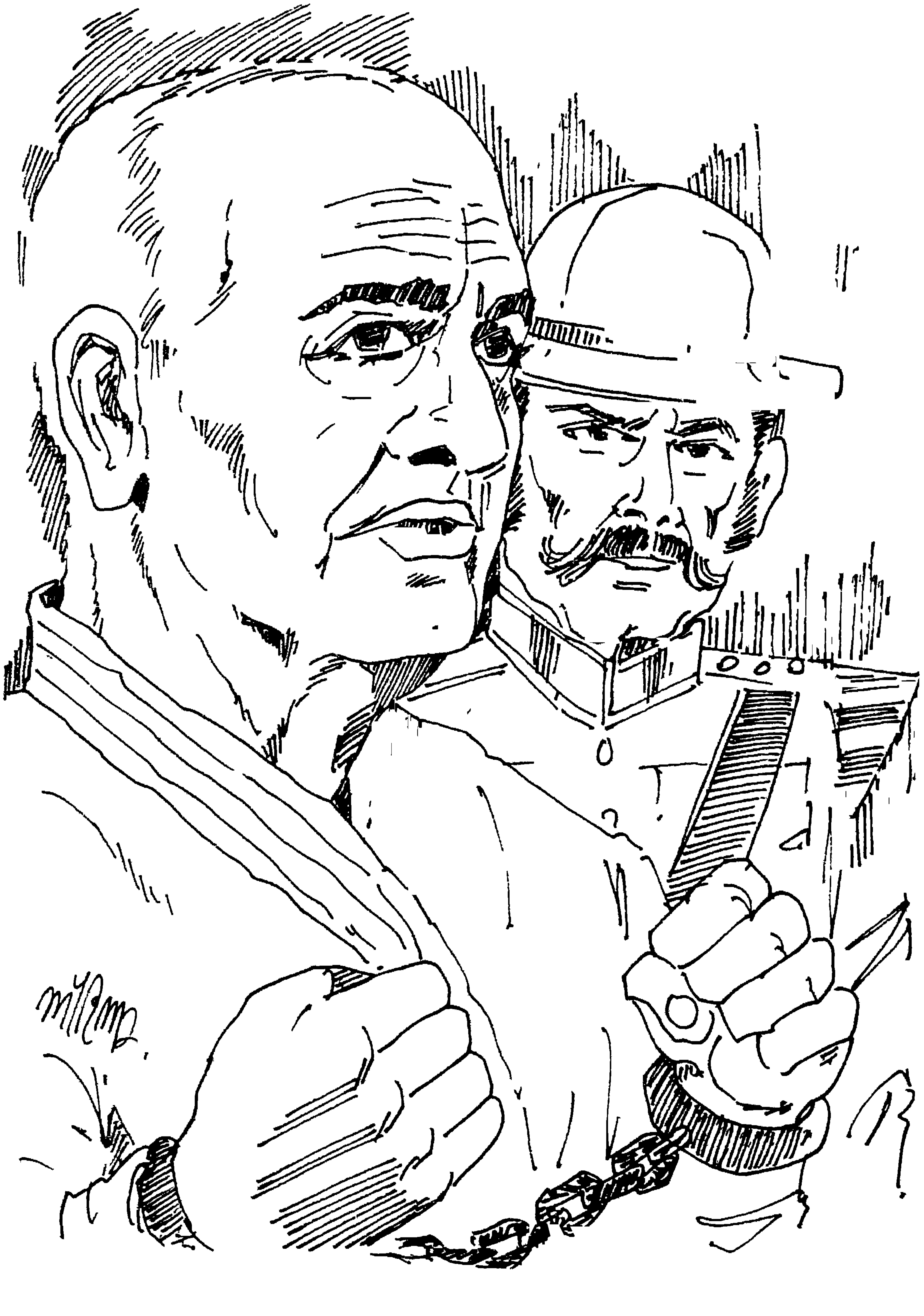

ने जनता को बताया कि महात्मा गाधी राष्ट्रीय स्वाधीनता आन्दोलन को प्रारम्भ करने उन लोगो के पास आ रहे है तो वे लोग प्रसन्नता के अतिरेक से नाच उठे। पटेल के पहुचने पर जनता मे जो एकता और सगठन की प्रवृत्ति उभरी उसे देखकर ब्रिटिश सरकार घबरा गई। अत जैसे ही सरकार को पता लगा कि 7 मार्च को पटेल के सम्मान मे रास गाव मे एक विशाल सभा का आयोजन किया गया है। कमिश्नर ने आदेश जारी कर दिया कि पटेल वहा भाषण नही देगे। इस आदेश से जनता मे आक्रोश भर गया। लोग कई गुने जोश के साथ घरो से निकल पडे और 7 मार्च को रास गाव मे इतनी विशाल सभा जुटी कि पटेल को इसका अनुमान तक न था।

पटेल जैसे दवग नेता प्रशासन की धमकियो से डरने वाले तो थे नही, फिर जनता का उमडता उत्साह देखकर उनका जोश उबाल पर आ गया। उन्होने सरकारी आज्ञा का उल्लघन कर जोरदार भाषण दिया। ये विदेशी शासक हम पर प्रतिबन्ध लगाते हैं कि हम अपने देश-भाइयो से बात तक न करे, उनके दु ख-दर्द न सुने, उनके समक्ष भाषण न दे। ऐसी अन्यायी सरकार के आदेशो को मै खुला उल्लघन करता हू। सरकार मे दम हो तो आगे वढे और मुझे कैद करे।

सरदार पटेल की चुनौती रग लाई। कमिश्नर ने उनकी गिरफ्तारी का आदेश जारी कर दिया और पटेल गिरफ्तार कर लिए गए।

गुजरात की जनता अपने प्रिय नेता की गिरफ्तारी पर बोखला उठी। साबरमती के रेतीले तट पर अहमदाबाद मे 75,000 स्त्री-पुरुष एकत्रित हुए और उन्होने सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया, 'हम अहमदाबाद के नागरिक यह सकल्प करते है कि जिस पथ पर वल्लभभाई पटेल गए है, हम भी उसी पर जाएगे और ऐसा करते हुए स्वाधीनता प्राप्त करके रहेगे। हम देश को स्वाधीनता दिलाए

विना न तो स्वय चेन से बेटेंगे और न ही सरकार को चैन से बैठने देंगे।'

दांडी यात्रा

गाधी जी अपने निश्चय के अनुसार धोषित तिथि पर साबरमती आश्रम से चल पडे और कई दिन लम्बी यात्रा पूरी कर दाडी जा पहुचे। उनके साथ 79 अन्य साथी थे। 6 अप्रैल को दाडी मे नमक बनाने का काम शुरू कर उन्होने सरकारी कानून को तोडा और वे गिरफ्तार कर लिए गए। उनके पीछे काग्रेस पार्टी खडी थी, अत. काग्रेस के वरिष्ठ नेताओ को पकड-पकडकर जेलो मे डाल दिया गया।

प॰ जवाहरलाल नेहरू गिरफ्तार हुए तो प॰ मोतीलाल नेहरू ने काग्रेस की अध्यक्षता सभाली और जब मोतीलाल नेहरू गिरफ्तार हुए तो उन्होने सरदार पटेल को अपना उत्तराधिकारी धोषित कर काग्रेस की लगाम उनके हाथो मे दे दी।

26 जून, 1930 को सरदार पटेल साबरमती जेल से रिहा कर दिए गए।

अब सरदार पटेल का पूरा ध्यान सगठन और काग्रेस की आर्थिक दशा मजबूत बनाने पर गया। उन्होने अपनी शक्ति अधिक-से-अधिक सदस्य बनाने तथा धन इकट्ठा करने मे झोक दी। लगभग सभी नेता जेल मे थे, अत सविनय अवज्ञा आन्दोलन के सचालन की जिम्मेदारी पूरी तरह पटेल के कधो पर आ गई। उन्होने देश के विभिन्न स्थानो का दौरा कर काग्रेस की सदस्यता बढाने पर जोर दिया और लोगो को जगाया कि जब सारे नेता जेल मे है, हम निकलकर बाहर आए और विदेशी सरकार को दिखा दे

कि 35 करोड की जनसख्या वाला यह देश एक है।

बम्बई मे छात्रो से आन्दोलन मे उतर आने की अपील करते हुए पटेल ने कहा, "इस समय जबकि युवको का युवराज जवाहरलाल जेल मे है तथा सैकडो माताओ पर पुलिस ने अमानुषिक अत्याचार किए है, तो तुम गणित और इतिहास पढने मे व्यस्त हो। छोड दो यह सब और निकलकर बाहर आओ, देश तुम्हे पुकार रहा है।"

पटेल की अपील पर हजारो छात्र पढाई छोडकर सविनय अवज्ञा आन्दोलन मे कूद पडे।

31 जुलाई, 1930 को लोकमान्य बाल गगाधर तिलक की जयन्ती के अवसर पर पटेल बम्बई मे एक जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे। जुलूस मे मदनमोहन मालवीय, जयरामदास, दौलतराम, शेरवानी आदि अनेक नेता शामिल थे। बोरीबन्दर स्टेशन के निकट पहुचते ही जुलूस को सरकार ने गैरकानूनी घोषित कर दिया, परन्तु सरदार पटेल अड गए और उन्होने सरकारी आदेश मानने से इन्कार कर दिया। पुलिस ने जुलूस को आगे नही बढने दिया तो सब लोग वही बैठ गए। पूरी रात मूसलाधार वर्षा होती रही, परन्तु कोई भी जुलूस मे से हिला तक नही। प्रातःकाल होते ही पुलिस ने जुलूस पर लाठी-चार्ज किया और जुलूस का नेतृत्व करने के जुर्म मे पटेल को गिरफ्तार कर लिया।

नवम्बर मे वे जेल से छूटे और तुरन्त सरकार विरोधी प्रचार मे लग गए। सरकार पटेल के धुआधार प्रचार से फिर सरकार घबराई और दिसम्बर, 1930 मे पटेल को गिरफ्तार किया। अबकी बार उन्हे नौ महीने की जेल हुई।

25 जनवरी, 1931 को गाधी जी को तथा काग्रेस कार्यसमिति के अनेक सदस्यो को छोड दिया गया।

5 मार्च, 1931 को गाधी इर्विन समझौता हुआ, जिसकी एक

शर्त के अनुसार जेलों में बन्द सभी सत्याग्रहियों को रिहा कर दिया गया। इसी आधार पर पटेल भी जेल से रिहा कर दिए गए।

31 मार्च, 1931 को कराची में अखिल भारतीय कांग्रेस का 46वां अधिवेशन हुआ, जिसमें सरदार वल्लभभाई पटेल को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया।

अब बारडोली का सरदार समूचे भारत का सरदार बन गया।

गांधी-इर्विन समझौते के ठीक बाद कराची सम्मेलन हुआ था। यदि स्थितियां सामान्य रही होती तो कांग्रेस के नेता तथा कार्यकर्ताओं में प्रसन्नता की लहर होती, परन्तु इस समझौते के ठीक बाद दो ऐसी घटनाएं घट गईं जिन्होंने भारतीय जनमानस को झकझोर दिया।

एक 23 मार्च, 1931 को भगतसिंह, राजगुरु तथा सुखदेव जैसे महान क्रान्तिकारी नेताओं को फांसी पर लटका दिया गया और उनकी लाशों को बड़े अमानवीय ढंग से चोरी छिपे जलाया गया। दूसरे कानपुर में हिन्दू-मुस्लिम दंगा इतना भयानक रूप ले गया कि उग्र मुस्लिम आततायियों ने गणेशशंकर विद्यार्थी जैसे सौम्य व्यक्ति की हत्या कर दी। 29 मार्च को उनका शव मिला। इन दोनों घटनाओं की देशभर में भारी प्रतिक्रिया हुई। युवकों में भारी रोष था। जनता अंग्रेज़ सरकार से और कांग्रेस से भी नाराज थी। कांग्रेस सरकार से समझौते कर रही थी और सरकार उसी देश में विद्वेष फैला रही थी, जिसकी सुरक्षा करना उसका दायित्व था।

अपने अध्यक्ष चुने जाने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं तथा प्रतिनिधियों को धन्यवाद देते हुए पटेल ने कहा कि उन्हें अध्यक्ष चुनकर देश ने समूचे गुजरात प्रान्त को सम्मानित किया है।

क्रान्तिकारियों को कुचलने की सरकार की क्रूरता पर प्रहार करते हुए पटेल ने कहा, "भगतसिंह और उनके साथियों की

देश-भक्ति, साहस और बलिदान के आगे मेरा सिर झुक गया है। लगभग सारे देश की यह माग थी कि इन नौजवानो की फासी की सजा आजन्म कारावास मे बदल दी जाए, परन्तु सरकार नही मानी और उसने इन्हे फासी पर लटका दिया। इससे पता लगता है कि इस सरकार की शासन प्रणाली कितनी हृदयहीन है।"

सम्मेलन मे उन्होने गाधी-इर्विन समझौते को स्वीकार करने, अहिसा के आधार पर आगे की लडाई लडते जाने तथा हिन्दू-मुस्लिम एकता बनाए रखने पर बल दिया।

इस समय काग्रेस मे सन्तुलन बनाए रखना और उसकी बागडोर सम्भालना कठिन कार्य था। काग्रेस भारी मतभेद के दौर से गुज़र रही थी। गाधी-इर्विन समझौता बहुत से नेताओ को मान्य न था। ऐसे मे सन्तुलन और धैर्य के अवतार सरदार पटेल ने काग्रेस को दृढ़ता प्रदान कर स्वाधीनता की ओर बढते कदमो का नई गति दी।

सरदार पटेल गाधी जी के अनुयायी और अहिसा की शैली मे पूरी तरह विश्वास रखने वाले होते हुए भी अपनी कार्य शैली के मामले मे विशेष थे। अनुशासन उनकी प्रथम शर्त थी। पार्टी मे अनुशासनहीनो के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करने के लिए उनकी आलोचना तक हो जाती थी, पर वे अनुशासनात्मक कार्यवाही करने मे कभी चूकते न थे।

वल्लभभाई पटेल अंग्रेजी सरकार की बदनीयती पर विशेष ध्यान रखते थे। सरकार की कथनी-करनी मे अन्तर था। उसके मन मे भारत व भारत की जनता के प्रति कोई सद्‌भाव न था। समझौते भी सरकार मजबूरी में करती थी और मागे भी मजबूरी मे ही मानती थी। अत· पटेल सरकार पर अधिक विश्वास करके नही चलते थे।

दिसम्बर, 1931 में गोलमेज सम्मेलन मे भाग लेने के लिए

गाधी जी इग्लैण्ड चले गए थे, भारत की चुनौती भरी स्थितियो से निबटने की जिम्मेदारी मुख्यत सरदार पटेल की थी।

सरकारी जुल्म बढ रहे थे, देश के हालात बिगड रहे थे। बारडोली के किसानो की समस्या को सरकार अभी तक उलझाए हुए थी, तथा उन दिनो बगाल की स्थिति भी भयकर थी।

4 जनवरी, 1932 को गाधी तथा काग्रेस अध्यक्ष सरदार पटेल को फिर गिरफ्तार कर लिया गया।

जनवरी, 1932 से मई, 1933 तक सोलह महीने महात्मा गाधी और सरदार पटेल यरवदा जेल में एक साथ रहे। जेल मे सरदार पटेल ने महात्मा गाधी की बहुत देखभाल की कि जो उनके लिए एक यादगार बन गई।

1 अगस्त, 1933 को पटेल को यरवदा जेल से हटाकर नासिक जेल मे भेज दिया गया। नासिक जेल से 14 जुलाई, 1934 को उन्हे रिहा किया गया। जनवरी, 1932 से जुलाई, 1934 तक देश में तथा राजनीतिक क्षेत्र मे अनेक महत्त्वपूर्ण घटनाए हो चुकी थी। 1 नवम्बर, 1932 को पटेल की माता का देहान्त हुआ और जब वे नासिक जेल मे थे तो 20 अक्टूबर, 1933 को उनके अग्रज विट्ठलभाई पटेल का वियना मे देहान्त हो गया। वियना से विट्ठलभाई पटेल का शव बम्बई लाया गया था और वहा बडी संख्या मे काग्रेस के सदस्यो तथा बम्बई के लोगो ने उनकी अत्येष्टि मे भाग लिया। सरदार पटेल अपने बड़े भाई की अत्येष्टि मे शामिल होने के लिए बहुत व्याकुल हुए, परन्तु क्रूर ब्रिटिश सरकार ने उन्हें शामिल नही होने दिया।

16 अगस्त, 1932 को सरकार ने साम्प्रदायिक पचाट घोषित किया। इसका विरोध करने के लिए गाधी जी ने जेल मे ही आमरण अनशन पर बैठ गए और सरकार को गाधी के साथ पूना

समझौता करना पड़ा। 15 मार्च, 1933 को ब्रिटिश सरकार ने एक श्वेत-पत्र प्रकाशित किया, जिसमे भारत के भावी सविधान की रूप-रेखा प्रस्तुत की गई थी।

यह एक ऐसा दौर था, जब काग्रेस मे परिवर्तनवादी गाधी जी का खुला विरोध करने लगे थे और पार्टी पर से गाधी जी की पकड कम होती जा रही थी।

काग्रेस का एक वर्ग पचाट को पूरी तरह अस्वीकार करना चाहता था। परन्तु सरदार पटेल और गाधी जी का रुख सख्त नही था। इससे काग्रेस मे मतभेद बढ गए। मदनमोहन मालवीय तथा एम एस अणे ने काग्रेस पार्लियामेण्ट्री बोर्ड से इस्तीफा दे दिया और काग्रेस नेशलिस्ट पार्टी बना ली।

17 सितम्बर, 1934 को गाधी जी ने वर्धा मे एक वक्तव्य प्रकाशित किया, जिसमे स्पष्ट सकेत था कि वे अब काग्रेस से अलग होना चाहते है क्योकि कुछ लोग उनके विचारों से सहमत नही है।

गाधी जी के इस स्पष्टीकरण के अनेक अर्थ निकाले गए। परन्तु पटेल ने बहुत स्पष्ट कर दिया कि वे गाधी जी पर कोई नैतिक दबाव देने के पक्ष में नहीं है। वे मानते है कि गाधी जी पूरी तरह सक्षम और समर्थ है, वे जो भी फैसला लेगे, वह पार्टी व देश के हित मे अवश्य होगा। इसलिए यदि उन्होंने काग्रेस से अलग होने का फैसला लिया है तो वह निश्चय ही काग्रेस के हित मे होगा।

अप्रैल, 1936 मे वर्धा मे काग्रेस कार्यसमिति ने पार्लियामेण्ट्री बोर्ड का गठन किया। वल्लभभाई पटेल अध्यक्ष चुने गए तथा गोविन्द वल्लभ पत सचिव। इस बोर्ड का कार्य भारतीय शासन अधिनियम 1935 के आधार पर प्रान्तीय सभाओ के चुनाव हेतु

प्रत्याशियों का चयन करना था। बोर्ड के अन्य सदस्य थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर असारी, डॉक्टर राजेन्द्रप्रसाद तथा मदनमोहन मालवीय। इस समय सरदार पटेल बीमार थे, परन्तु उन्होने एक दिन भी आराम नही किया। बीमारी की हालत में ही उन्होने पजाब, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रान्त, महाराष्ट्र, मद्रास तथा अन्य क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होने योग्य प्रत्याशियों को चुनाव के लिए आगे लाने तथा दलीय एकता व अनुशासन बनाए रखने के लिए रात-दिन एक कर दिया। अधिक-से-अधिक कांग्रेस सदस्यो को मतदाता सूचियो मे शामिल करने से लेकर चुनावो की उचित व्यवस्था करने तक सारे कार्य पटेल की देख-रेख मे सम्पन्न हुए।

वल्लभभाई पटेल के विशेष प्रयासो, गाधी जी के नैतिक दबाव, भारतीय जनता की निरतर बढती जागरूकता तथा क्रान्तिकारियो की बडी-बडी कुर्बानियो ने ब्रिटिश सरकार को सोचने पर मजबूर कर दिया था कि भारत को पूरी स्वाधीनता नही तो कम-से-कम शासन मे भागीदारी तो दी ही जाए। ब्रिटेन के प्रधानमन्त्री के नेतृत्व मे ब्रिटिश पार्लियामेण्ट ने भारत के भावी शासन विधान पर विचार किया और 30 जुलाई, 1935 को गवर्नमेट ऑफ इण्डिया एक्ट नामक अधिनियम इग्लैण्ड की ससद के दोनो सदनो मे पारित हो गया। इसके अनुसार भारतीय प्रान्तो को काफी सीमा तक स्वतन्त्रता देकर केन्द्रिय शासन मे प्रान्तो व देशी राज्यो का सघ बनाने की योजना बनाई गई थी। यद्यपि कांग्रेस इस अधिनियम के तहत चुनावो मे भाग लेने के मामले मे अभी तक एकमत नही थी, परन्तु फिर भी शीर्ष नेताओ ने फैसला ले लिया था और चुनावो की तैयारिया होने लगी थी।

कांग्रेस का 49वा अधिवेशन 9 से 14 अप्रैल, 1936 तक प जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता मे लखनऊ मे हुआ। इसमे कांग्रेस

के चुनाव मे भाग लेने तथा प्रान्तीय सरकारो मे पद ग्रहण करने की स्वीकृति दे दी गई।

इन्ही दिनो प॰ जवाहरलाल नेहरू का रुझान साम्यवाद की ओर तेजी से बढने लगा और ऐसा लगने लगा कि वे कांग्रेस के कार्यक्रमो तथा कांग्रेस द्वारा प्रान्तीय सरकारो के सचालन मे साम्यवादी नीतियो को प्राथमिकता देगे। जबकि सरदार पटेल साम्यवाद के कट्टर विरोधी थी। अत देशभर मे यह चर्चा फैल गई कि प॰ जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल मे मतभेद पैदा हो गए है।

दिसम्बर, 1936 मे फैजपुर मे कांग्रेस का 50वा अधिवेशन होना था। इस समय यह चर्चा फैली कि इसके अध्यक्ष वल्लभभाई पटेल बनाए जाएगे।

परन्तु गाधी जी के अनुरोध पर वल्लभभाई ने अपना नाम वापस ले लिया और प॰ जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता की सिफारिश की।

फरवरी, 1937 मे चुनाव परिणाम घोषित हुए। ग्यारह मे से छ प्रान्तो मे कांग्रेस को बहुमत प्राप्त हुआ।

7 जुलाई, 1937 को कांग्रेस ने छ प्रान्तो मे मन्त्रिमण्डल बनाने का निर्णय लिया, परन्तु गवर्नरों ने एक अडगा अडा दिया। हर सरकार गवर्नर के प्रति उत्तरदायी होगी तथा गवर्नर को विशेषाधिकार का इस्तेमाल करने की खुली छूट होगी।

13 सितम्बर, 1938 तक ग्यारह मे से आठ प्रान्तो मे कांग्रेस की सरकारे बन गई।

बम्बई प्रान्त मे कांग्रेस का मन्त्रिमण्डल बनते ही सरदार पटेल ने सबसे पहला काम यह किया कि 1932 व 1934 के बीच पिछले सत्याग्रह के दौरान जिन किसानो की जमीने सरकार ने जब्त करके बेच डाली थी, उन्हे उनकी जमीने वापस दिलवा दी।

सरदार पटेल अपनी दृढता तथा न्यायप्रियता के लिए सदैव चर्चा मे रहे। जब सिद्धान्त की बात आ जाती थी, तब वे न परिणाम की चिन्ता करते थे और न ही सम्बन्धो मे आने वाली कड़वाहट की।

कांग्रेस पार्लियामेण्ट्री बोर्ड के अध्यक्ष के रूप मे उन्हे कई बार बडे कडवे फैसले लेने पडे और कठोर कदम उठाने पडे। कांग्रेस के मन्त्रियों को कठोर अनुशासन मे रखने का दायित्व उन्होने बडी सफलतापूर्वक निभाया।

1938-39 मे एक ऐसा दौर भी आया जब भारतीय रियासतो की जनता को देशी राज्यो मे अच्छा शासन पाने के लिए आन्दोलन करने पडे। देशी राज्यो के विरुद्ध इन आन्दोलनो का नेतृत्व सरदार पटेल ने बडी सफलतापूर्वक किया। 1934 तक देशी राज्यो की जनता भी जागरूक हो उठी थी, जब ब्रिटिश शासित क्षेत्रो की जनता सरकार के खिलाफ आन्दोलनो मे लगी थी, सरकार से अनेक सुविधाए लेने मे सफलता प्राप्त कर रही थी। तब देशी राज्यो की जनता भी अपने अधिकारो के लिए मचलने लगी।

देशी राज्यो की जनता को भारतीय शासन अधिनियम 1935 लागू हो जाने के बाद भी राज्यों मे प्रतिनिधि चुनने का अधिकार नही दिया गया था।

1937 मे चुनावो के बाद जब विभिन्न प्रान्तो मे कांग्रेस की सरकारे बन गई तो रियासतो की प्रजा मे विशेष रूप से जागरूकता आने लगी। यद्यपि गाधी जी तथा वल्लभभाई पटेल अब तक देशी रियासतो की जनता के आन्दोलन को कांग्रेस का सहयोग देने के पक्ष मे थे, परन्तु कांग्रेस की सरकारे गठित हो जाने तथा देशी राज्यो की जनता मे आन्दोलन की परिपक्वता आ जाने के बाद वल्लभभाई ने कांग्रेस द्वारा देशी राज्यो की जनता के हित के लिए

आन्दोलन का नेतृत्व किया जाना स्वीकार कर लिया।

सबसे पहले अक्टूबर, 1937 मे कलकत्ता मे कांग्रेस महासमिति ने मैसूर रियासत मे राजा की निरकुशता के विरुद्ध प्रस्ताव पारित किया और वहां की प्रजा के आन्दोलन को सहयोग देने का फैसला लिया।

परन्तु कुछ कारणो से स्थिति स्पष्ट न हो सकी। कांग्रेस मे कुछ लोग देशी रियासतो की जनता को खुला सहयोग देने के पक्ष मे थे, कुछ इसके विरोधी थे।

वल्लभभाई सक्षम नेता थे। वे चाहते तो सीधे ही देशी रियासतो की जनता का नेतृत्व कर उन्हे देशी राजाओ के निरकुश राज्य से मुक्ति दिलाने मे जनता की मदद कर सकते थे। परन्तु इससे देशी राजाओ के कांग्रेस विरोधी हो जाने और ब्रिटिश राज्य के नियन्ताओं के चुगुल मे फस जाने का डर था। स्थिति बडी नाजुक थी, रियासती जनता के कष्टो के निवारण के लिए कांग्रेस कुछ न करे तो कांग्रेस पर पक्षपात का आरोप लगता था कि वह देशी रियासतो की जनता के दुःख-दर्द दूर नही करना चाहती और यदि देशी राजाओं से सीधी दुश्मनी लेते हुए कांग्रेस वहा की जनता के साथ आन्दोलन मे सीधी उतर जाए तो देशी राजाओ के साथ विश्वास भग होने का खतरा था। स्वाधीनता की ओर कदम-दर-कदम बढ रहे सुधारवादी सत्याग्रह को बडी सूझ-बूझ के साथ चलाया जा रहा था। विदेशी शासको के चगुल से देश को आजाद कराना ही लक्ष्य था और लडाई इस प्रकार लडी जा रही थी कि हर बार शासक की पकड कुछ कम हो जाए और शासितो की पकड कुछ बढ जाए।

इस पूरी प्रक्रिया मे देशी राजा या तो तटस्थ थे या फिर कांग्रेस से सहानुभूति रखते थे। ऐसे मे उनके विरुद्ध आन्दोलन को सहयोग देना स्वाधीनता आन्दोलन मे देशी राजाओ की सहानुभूति

खो देना होता। अंग्रेज तो यही चाहते थे कि कांग्रेस उग्र हो जाए और वह देशी राजाओं से टकरा जाए और देशी राजाओं की ताकत भी अंग्रेजों की ताकत बन जाए।

परन्तु वल्लभभाई पटेल जैसे धीर, वीर और गम्भीर नेता आगे तक की सोचकर चलते थे और फूंक-फूंककर कदम रखते थे। उन्होंने बीच का रास्ता निकाला। एक ऐसा रास्ता जिसमें कांग्रेस देशी राजाओं की दृष्टि में खटके भी नहीं और देशी रियासतों की जनता स्वयं ही अपने शासकों से टकराकर उनकी शक्ति को धीरे-धीरे तोड़ने लगे और एक दिन ऐसा आ जाए कि देशी राजा कमजोर पड़ जाएं और अपनी जनता के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएं। इस शैली में यह खतरा भी नहीं था कि देशी राजा बौखला जाएंगे और मदद के लिए अंग्रेजों के पास दौड़ेंगे। वे धीरे-धीरे अपनी जनता से निबटते रहेंगे और एक-एक कर जनता अपने अधिकार उनसे लेती चली जाएगी।

देशी रियासतों की प्रजा ने अपनी लड़ाई अपने-आप आरम्भ कर दी। 1938-39 में मैसूर, ट्रावनकोर, कश्मीर, हैदराबाद, जयपुर, उदयपुर, उड़ीसा आदि देशी राज्यों की जनता ने प्रजा परिषदों द्वारा अभूतपूर्व जागृति आई।

अन्ततः 1939 में त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस ने देशी रियासतों की जनता के आन्दोलन को सहयोग देने वाला प्रस्ताव पारित कर दिया और कांग्रेस इन आन्दोलनों के पीछे आ खड़ी हुई।

वल्लभभाई पटेल उस समय देशी राजाओं की दृष्टि में कांग्रेस के सबसे अधिक सुलझे हुए नेता माने जाते थे। अतः जनता के आन्दोलन की उग्रता को कम करने तथा कुछ और अधिकार देकर जनता के साथ समझौता करने में वे पटेल का सहयोग चाहने लगे। पटेल के नेतृत्व में कांग्रेस कूटनीति की यह भारी विजय थी।

पटेल देशी राजाओ को अपना मित्र मानते थे तथा उनके अन्दर यह भावना भरने मे कामयाब रहे थे कि वे ब्रिटिश सरकार के गुलाम है और इस गुलामी से निकलने के लिए उन्हे प्रयास करने चाहिए। देशी रियासतो की जनता की मागो को उचित ठहराते हुए पटेल ने देशी राजाओ को स्पष्ट सकेत दे दिया था कि उनके राज्यो की जनता उनकी शत्रु नही है, जनता को अधिकार दे देने से राज्यो की स्वाधीनता की लडाई मे जनता आगे बढकर हिस्सा लेगी और राज्यो को अग्रेजों के चगुल से छुडाना आसान हो जाएगा।

मई, 1938 मे पटेल ने मैसूर रियासत मे जनता के आन्दोलन का नेतृत्व कर रही काग्रेस तथा राज्य सरकार के बीच समझौता करवाया।

इसी प्रकार पटेल ने अपने सुलझे हुए व्यक्तित्व द्वारा देश के अन्य देशी रियासतो की समस्याओ का समाधान ढूंढा। राजकोट की जटिल समस्या का समाधान भी पटेल ने तलाशा। काठियावाड की लीमडी रियासत के साथ लम्बा सघर्ष कर उसके सुलझाने का प्रयास किया। इस संघर्ष में तो पटेल की जान को भी खतरा हो गया था। जब स्थिति कुछ सुलझने लगी तो मुसलमानो को पटेल के विरुद्ध भड़का दिया गया। कुछ कट्टर मुसलमानों ने पटेल को जान से मारने की योजना बना ली।

14, मई 1939 को भावनगर मे प्रजा परिषद की बैठक आयोजित की गई। उसकी अध्यक्षता करने के लिए सरदार पटेल को आमन्त्रित किया गया। जैसे ही पटेल एक कार मे मस्जिद के सामने से गुजरे, कुछ मुसलमान अचानक जुलूस पर टूट पडे। इससे अनेक लोग ज़ख्मी हुए तथा एक की मृत्यु हुई।

यहा की स्थिति की सूचना तार द्वारा गाधी जी को देते हुए सरदार पटेल ने कहा, "सवेरे यहा पहुचा। सभी वर्ग के लोगो ने

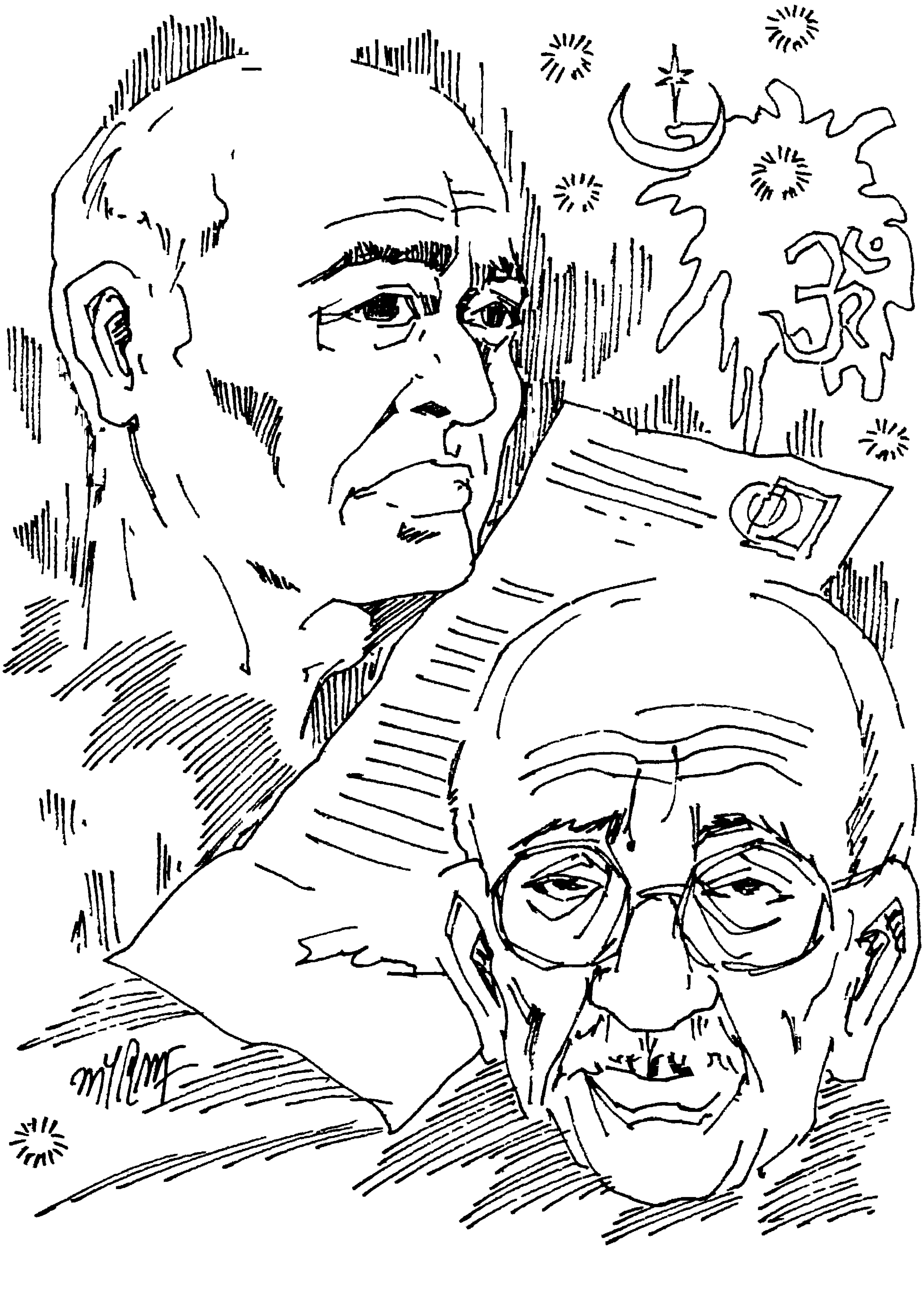

उत्साहपूर्वक स्वागत किया। जुलूस का बडा भाग मस्जिद के सामने से गुजर चुका था। जैसे ही मेरी कार मस्जिद के सामने पहुचने लगी, कुछ मुसलमान पहले से तय की गई योजना के अनुसार बाहर निकल आए और लाठियो, कुल्हाड़ो व छुरो से जुलूस पर टूट पडे। नानाभाई मेरी कार के आगे थे। उन्हे गन्दी चाल की कुछ गन्ध आ गई थी। इसलिए वे मस्जिद के सामने ही खडे हो गए। उन लोगो ने उनसे वहा से हट जाने को कहा, परन्तु उन्होने मेरी कार सही सलामत गुजर जाने तक वहा से हटना नामजूर कर दिया। तुरन्त उनके सिर पर लाठी का प्रहार हुआ.. दूसरे भाइयो को भी सख्त चोटें आई है। एक की मृत्यु हो गई है और एक की स्थिति बहुत गम्भीर है।"

वास्तव मे कट्टर मुस्लिमलीग जनता की समस्या के समाधान का श्रेय काग्रेस को नही लेने देना चाहती थी, इसीलिए उसके सदस्य इतने उग्र हो गए।

समाजवादियों से मतभेद

सरदार वल्लभभाई पटेल पूरी तरह अनुदारवादी तथा दक्षिणपन्थी थे। मई, 1934 मे अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी के अधिवेशन के अवसर पर पटना मे आचार्य नरेन्द्रदेव ने समाजवादी सोच के काग्रेसियो का एक समानान्तर सम्मेलन बुलाकर 'अखिल भारतीय काग्रेस सोशलिस्ट पार्टी' के गठन की घोषणा कर दी थी। प्रसिद्ध समाजवादी नेता श्री जयप्रकाश नारायण इस पार्टी के सगठन के मन्त्री बनाए गए थे। इसकी शाखाए देश के अन्य भागो मे भी खुल गई। इस सगठन मे काग्रेस के अनेक प्रखर सोच वाले नेता अपनी अलग पहचान बनाते हुए शामिल हो गए थे। गाधी जी ने देश मे

दलीय एकता बनाए रखने के उद्देश्य से इस पार्टी का गठन का स्वागत भी कर दिया था।

परन्तु सरदार पटेल की पटरी समाजवादियो के साथ कभी नही बैठ पाई। उनके अनुसार 'समाजवादियो का दर्शन' पुस्तक पाडित्य मात्र था। जनता व देश की समस्याओं की व्यावहारिक समझ उसमे न थी।

समाजवाद को एक अनबूझ पहेली करार देते हुए उन्होने कहा था, "समाजवाद की व्याख्या के बारे मे सारे समाजवादी एकमत नही है। भिन्न-भिन्न लोग इसका भिन्न-भिन्न अर्थ करते है। ब्राह्मणो में चौरासी जातिया है, जबकि समाजवादी पिचासी जातियों के मालूम होते है। इसलिए ऐसे समाजवाद के बारे मे राय देना कठिन है।"

गुजरात मे समाजवादियो ने अपनी शाखा खोल दी थी। पटेल उस समय जेल मे थे, परन्तु जेल से छूटने के बाद उन्होने गुजरात का दौरा किया और समाजवाद की कटु आलोचना की।

पटेल का स्वभाव एक मामले मे गाधी जी से सर्वथा भिन्न था। गाधी जी अपने शत्रुओ के प्रति भी सहानुभूति रखते थे जबकि सरदार पटेल अपने किसी भी विरोधी के प्रति कोई सहानुभूति नहीं रखते थे।

1936 मे लखनऊ मे काग्रेस का अधिवेशन हुआ और वामपन्थ की ओर झुकाव वाले युवा नेता जवाहरलाल नेहरू को काग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। इससे समाजवादियो का उत्साह और जोश बहुत बढ गया। नेहरू जी ने काग्रेस की कार्यसमिति मे वल्लभभाई के विरोध के बावजूद जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेन्द्रदेव तथा अच्युत पटवर्धन जैसे कट्टर समाजवादी नेताओ को शामिल कर यह स्पष्ट सकेत दे दिया कि वे इस मामले में वल्लभभाई की नही सुनेंगे।

नेहरू जी ने अपने अध्यक्षीण भाषण मे समाजवाद की बडी तारीफ की और यहा तक कह डाला कि समाजवाद मे ही भारत जैसे गरीब और पिछडे हुए मुल्क की समस्याओ का समाधान निहित है।

सरदार पटेल एक गम्भीर नेता थे। वे किसी विचारधारा को लेकर उडने मे विश्वास नही रखते थे। भारत की जमीन जिस विचार के अनुकूल थी और भारतीय जनता व शासको की मानसिकता जिस विचार से मेल खाती थी, उसी विचार की धुरी पर वे काग्रेस के लिए चल रहे थे। समाजवाद को कभी भी उन्होंने अपनी जमीन से जुडा तथा गम्भीर दर्शन नहीं माना। उसके बचकानेपन की वे सदैव निन्दा करते रहे।

प० जवाहरलाल नेहरू जैसे नेता की काग्रेस मे विशेष जगह थी। नेहरू जी से पटेल के वैचारिक मतभेद थे, परन्तु वे कभी उनसे इस तरह नही टकराए कि काग्रेस की सगठनात्मक तथा वेचारिक एकता और आपसी समझ व समाहार शक्ति ही समाप्त हो जाए। पश्चात् समाजवाद को काग्रेस पर हावी होने तथा काग्रेस की जमीन छीन ले जाने से रोकने मे सरदार पटेल ने जो महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।

समाजवादी स्थापित व्यवस्था को ठोस विकल्प तैयार किए बिना ही विश्व की सबसे बडी साम्राज्यवादी ताकत से टकरा जाने के स्वप्न देखते थे, जबकि पटेल समझते थे कि बिखराव, विचार-वैभिन्य, साम्प्रदायिक मनमुटाव तथा पिछडे हुए जनमानस के साथ इतनी बड़ी ताकत से सीधे टकराकर भारतीय वह सब भी खो बैठेगे, जो अब तक पाया है।

धीरे-धीरे शत्रु की शक्ति को कम करते जाना और अपनी शक्ति को बढ़ाते जाने की शैली में पटेल को दृढ विश्वास था।

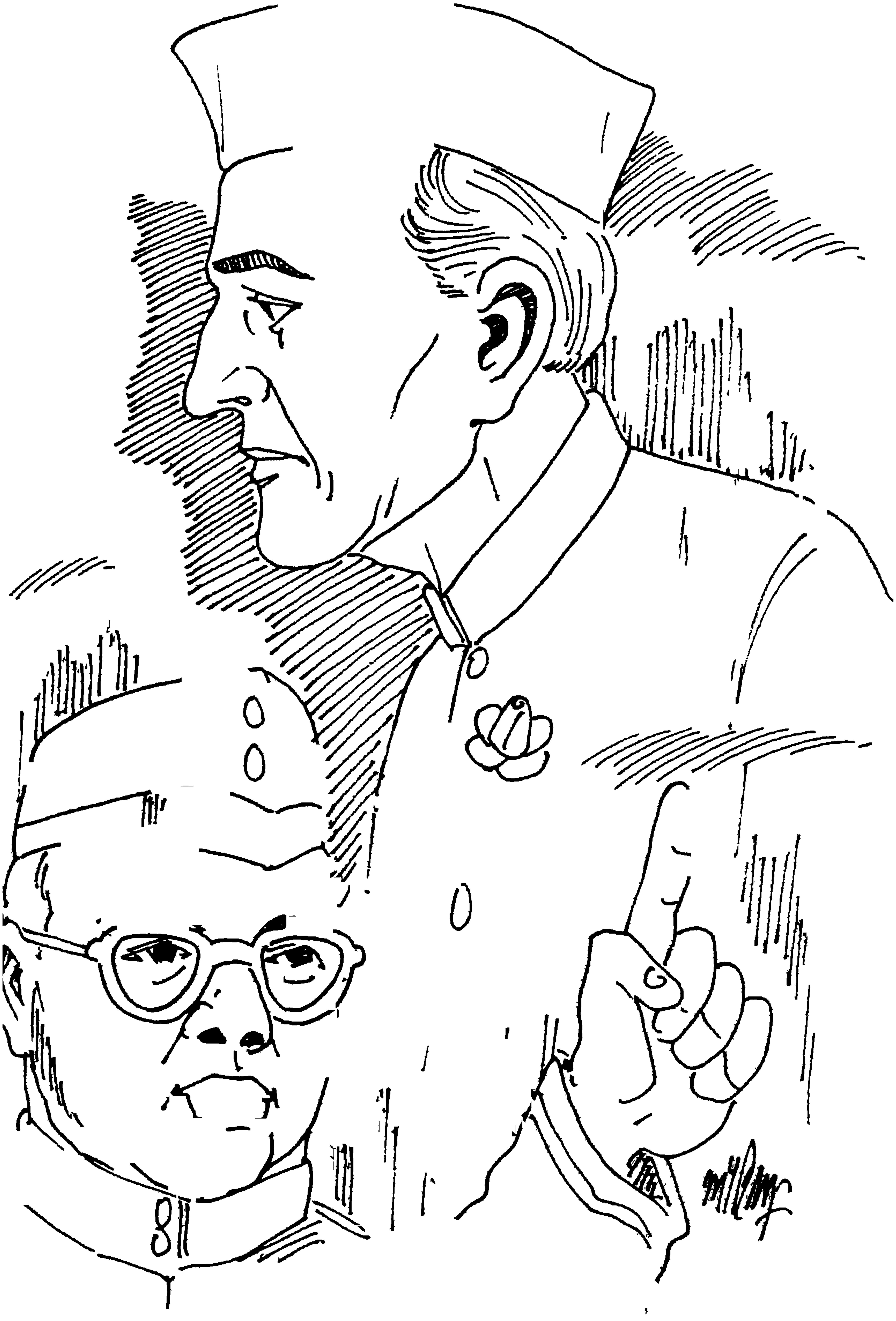

अपनी सफल वकालत को त्यागकर इसी सिद्धान्त पर चलते हुए उन्होंने राजनीति में अपनी पकड बनाई थी। महात्मा गाधी की इसी शैली पर विश्वास कर उन्होंने अपने-आपको गाधी के प्रति समर्पित कर दिया था। गाधी तथा गाधीवाद की अवहेलना उन्हे न पार्टी मे पसन्द थी, न देश मे।

सुभाषचन्द्र बोस से मतभेद

सुभाषचन्द्र बोस बहुत जोशीले और गर्म स्वभाव के नेता थे। वे गाधी जी के ध्रुव दक्षिण पन्थ को कभी नहीं पचा पाए। सरदार पटेल उनकी दृष्टि मे केवल गुजरात के नेता थे। गाधी जी की अन्धभक्ति ने उन्हे पुरस्कारस्वरूप पूरे देश पर लाद दिया है, ऐसा सुभाष का मत था।

सुभाषचन्द्र बोस व पटेल मे खुला वैचारिक मतभेद था। सुभाष काग्रेस को समाजवादी और क्रान्तिकारी पार्टी के रूप मे स्थापित कर अहिंसा या हिसा जैसे भी सम्भव हो, ब्रिटिश साम्राज्य से सीधा भिडा देना चाहते थे, उन्हे विश्वास था कि काग्रेस जैसी पार्टी यदि सीधी चुनौती ब्रिटिश साम्राज्य को दे दे तो क्रान्तिकारी और इस देश की जनता की ताकत काग्रेस को सीधी प्राप्त हो जाएगी और अंग्रेज़ो को मसलते देर न लगेगी।

जबकि पटेल गाधी जी की शैली मे केवल अहिसात्मक आन्दोलन के द्वारा सुधारात्मक शासन स्थापित करते-करते अपनी शक्ति को क्रमश बढाते हुए स्वाधीनता प्राप्त करने के पक्ष मे थे।

पटेल यह मानकर चलते थे कि सुभाष का रास्ता अराजकता का है। उखाड-पछाड और विनाश का रास्ता भारतीय जनता के अनुकूल साबित नही होगा और परिणामस्वरूप जो आन्दोलन गाधी

जी ने चलाया, वह पूरी तरह तहस-नहस हो जाएगा। वे आरम्भ मे भारत को ब्रिटेन का सघ बनाने के पक्ष मे था। उनका ख्याल था कि ऐसा करने से धीरे-धीरे देश आत्मनिर्भर होता जाएगा और फिर पूरी आजादी हासिल कर उसे सम्भालने मे सक्षम होगा।

जबकि सुभाषचन्द्र बोस सघ योजना के कटु विरोधी थे। वे सुधारवाद के कट्टर आलोचक थे। वे तो एक ही बार मे पूरी आजादी पाना चाहते थे। चाहे लड़कर हो, चाहे मरकर, चाहे मारकर।

21 जनवरी, 1939 को सुभाषचन्द्र बोस ने अगली बार अध्यक्ष पद की दावेदारी की घोषणा की तो सरदार पटेल ने सुभाष की दावेदारी का तीव्र विरोध किया।

सुभाषचन्द्र बोस फिर भी मैदान से नही हटे। चुनाव हुआ और उनके विरोधी तथा महात्मा गाधी तथा पटेल के प्रिय उम्मीदवार पट्टाभि सीतारमैया चुनाव हार गए तो गाधी जी ने कहा, "पट्टाभि सीतारमैया की हार मेरी हार है।"

इससे सुभाषचन्द्र बोस को बहुत पीडा हुई। वे बुरी तरह बीमार पड गए। त्रिपुरा काग्रेस अधिवेशन मे 10 मार्च, 1939 को सुभाष का अध्यक्षीय भाषण पढ़कर सुनाया गया। दूसरे दिन सरदार वल्लभभाई पटेल ने एक प्रस्ताव तैयार किया, जिसे अधिवेशन मे स्वीकार कर लिया गया।

इस प्रस्ताव मे लिखा था, "आगामी वर्ष मे सकटपूर्ण स्थिति उपस्थित हो सकती है। ऐसे सकट मे महात्मा गाधी ही काग्रेस और देश का नेतृत्व कर सकते है, इसलिए काग्रेस अत्यावश्यक समझती है कि काग्रेस की कार्यकारिणी मे गाधी जी का पूरा विश्वास हो और अध्यक्ष से निवेदन करती है कि इस वर्ष के लिए गाधी जी की इच्छा के अनुसार कार्यकारिणी का निर्माण करे।"

सुभाषचन्द्र बोस कठपुतली अध्यक्ष बने रहने को तैयार न थे, अत उन्होंने त्याग-पत्र दे दिया।

वल्लभभाई पटेल यद्यपि सुभाषचन्द्र बोस की एक अच्छे व्यक्ति और नेता के रूप मे भारी प्रशसा करते थे, परन्तु यह नही चाहते थे कि कोई काग्रेस का इस्तेमाल अपनी मन-माफिक के करे।

इस विषय मे महात्मा गाधी और वल्लभभाई पटेल के विचार बिल्कुल एक थे। पूरी दक्षिणपन्थी लॉबी इन्ही विचारो की थी। जवाहरलाल नेहरू तथा उनके पिता मोतीलाल नेहरू यद्यपि गाधी जी के इस रुख से सहमत नही थे, परन्तु पटेल के नेतृत्व मे जिस ढग से दक्षिणपन्थी लॉबी ने सुभाष को काग्रेस से उखाड फेकने की मुहिम चलाई, उसका खुला विरोध नेहरू जी ने नही किया।

सुभाष अलग हो गए, कॉग्रेस फिर से दक्षिणपन्थी लॉबी की पकड मे आ गई। 1 सितम्बर, 1939 को जर्मन ने पोलैण्ड पर आक्रमण करके द्वितीय विश्वयुद्ध छेड दिया। ब्रिटेन और फ्रास ने सयुक्त रूप से 4 सितम्बर को जर्मनी के विरुद्ध युद्ध घोषित कर दिया और इसी के साथ भारत के वायसराय ने जर्मनी के विरुद्ध भारत के युद्ध की घोषणा कर दी।

सरदार पटेल वायसराय की इस जल्दबाजी पर बिगड गए। उन्होने गरजते हुए कहा, "वायसराय कौन होता है भारत को युद्ध में झोकने वाला, यह देश कोई वायसराय की बपौती तो नहीं है। देश के चुने हुए प्रतिनिधियों से मशविरा किए बिना देश को युद्ध में झोकने के पीछे वायसराय की मशा क्या है? मैं यह स्पष्ट घोषणा करता हू कि जब तक ब्रिटिश सरकार भारत को उसकी स्वाधीनता का विश्वास नही दिला देती, भारत युद्ध मे भाग नही लेगा।"

वायसराय को वल्लभभाई पटेल की टिप्पणी खल गई। उसने गाधी जी को बुलाकर उनसे बातचीत की, परन्तु गाधी जी ने कुछ

भी स्पष्ट कहने से इन्कार कर दिया। गाधी जी ने इशारा किया कि काग्रेस की बागडोर उसके वरिष्ठ नेताओ के हाथ मे है, उनमे वल्लभभाई प्रमुख है। वायसराय को सलाह दी गई कि वह वल्लभभाई से बात करें।

4 अक्टूबर को वायसराय ने वल्लभभाई पटेल से बात की। इसके बाद 10 अक्टूबर की वर्धा मीटिग मे काग्रेस ने सरकार से युद्ध उद्देश्यो को स्पष्ट करने को कहा। इसके साथ ही काग्रेस ने युद्ध उपसमिति गठित की। प० जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष बने, वल्लभभाई पटेल और मौलाना अबुल कलाम आजाद इसके सदस्य थे।

16 अक्टूबर को वायसराय ने घोषणा की कि ब्रिटेन का उद्देश्य युद्ध के बाद भारत को औपनिवेशिक राज्य प्रदान करना है। औपनिवेशिक राज्य की बात कांग्रेस ने स्वीकार नही की और डॉक्टर राजेन्द्रप्रसाद की अध्यक्षता मे मन्त्रिमण्डल से त्याग-पत्र देने की घोषणा कर दी।

वायसराय की घोषणा के पश्चात् एग्लो इण्डियन तथा सरकार समर्पित अंग्रेजी समाचार-पत्रों ने इस तरह का मन्तव्य प्रकाशित करना आरम्भ कर दिया कि काग्रेस स्वार्थी हो गई है और वह अल्पसख्यको की उपेक्षा करके अपनी मागे मनवाना चाहती है। सरकार अल्पसख्यको के हितो की अनदेखी नही होने देगी। समाचार-पत्रो मे यह टिप्पणिया अंग्रेजो के इशारे पर प्रकाशित की गई थी। काग्रेस इस प्रहार से तिलमिला गई।

वरिष्ठ काग्रेसी नेता वल्लभभाई पटेल ने सरकार की कटु आलोचना की और कहा, "ब्रिटिश सरकार अल्पसख्यको की समस्या उठाकर भारत की आजादी की मूल समस्या पर पर्दा डालना चाहती है। यह सरकार उस चालाक बन्दर की भूमिका अदा कर रही है,

जो दो बिल्लियों को लडाकर दोनों का हिस्सा हडप गया था। परन्तु हम बिल्ली नही है, हमारे होते सरकार के ये मनसूबे कभी पूरे नही होगे।"

मुस्लिमलीग और देशी राजा दोनो के प्रति सरदार पटेल का दृष्टिकोण साफ होता चला गया था। वे समझ गए थे कि ये दोनो ही भारत की आजादी मे रोडा अटकाने वाली समस्याए पैदा कर रहे है। अत वे इनके प्रति अत्यधिक कठोर और सावधान हो गए।

विश्वयुद्ध मे दोनो महाशक्तियो मे से किसी के प्रति भी सरदार पटेल के मन मे सहानुभूति न थी। गाधी जी की सहानुभूति तो ब्रिटेन व फ्रास के साथ थी। गाधी जी कह चुके थे कि वे नाजीवादी ताकतो की हार तथा ब्रिटेन व फ्रास की विजय देखना चाहते है, परन्तु सरदार पटेल ने साफ-साफ कह दिया, "ब्रिटिश साम्राज्य और जर्मन नाजीवाद इन दोनो में से हिन्दुस्तान किसी को भी पसन्द नही करता। साम्राज्यवाद की मदद करके नाजीवाद का नाश करने मे सहायता कीजिए, तो हम यह कहेगे कि ऐसी हालत मे तुम दोनों ही लडकर मर जाओ।"

सरदार पटेल सुभाषचन्द्र बोस की तरह अग्रेजो की कमजोरी पर प्रहार कर झटके से आजादी छीन लेने के पक्ष मे भी न थे। उनका विचार था कि अग्रेजो की कमजोरी हमारी स्वाधीनता का आधार नही है। हमे अपनी कमज़ोरियां मिटानी है। अपने-आपको इतना मजबूत बनाना है कि हम आजादी ले सके और उसे सम्भाल सके।

हां, देश की एकता एव अखण्डता की चिन्ता उन्हे खाए जा रही थी। वे लम्बे समय से स्वाधीनता आन्दोलन से जुडे थे और यह देखकर दु खी होने लगते थे कि सब लोग एकजुट होकर आजादी

की माग क्यो नही करते। जब सारे भारत का एकमात्र उद्देश्य अग्रेजो को देश से बाहर करना और देश का आजाद करना है तो छोटे-छोटे स्वार्थो और मतभेदो को भुलाकर सब लोग एक महाशक्ति बनकर क्यों नही खडे होते?

पटेल देश की आजादी के बारे मे पूरी तरह आशावादी थे। जिस प्रकार आजादी के पौधे को रोपकर उसे पल्लवित और पुष्पित करने के लिए वे जीवनभर सघर्ष करते आए थे और उनके देखते-देखते सोया हुआ देश जागा था और सकल्पित होकर उठ खडा था, उससे वे पूरी तरह आशान्वित थे कि अग्रेजो को हिन्दुस्तान से जाना ही पडेगा, हिन्दुस्तान को सदा के लिए गुलाम बनाकर नही रखा जा सकता।

गाधी जी के प्रति सम्पूर्ण समर्पण और उनके सिद्धान्तो व विचारों मे समूची आस्था के मामले मे सरदार पटेल सबसे आगे थे। परन्तु द्वितीय विश्वयुद्ध के दिनो तक पहुचते-पहुचते अहिसा के प्रति विश्व की महाशक्तियो का रुख तथा मुस्लिमलीग की अवसरवादिता तथा हिसा द्वारा पूरे हिन्दू समुदाय पर भारी पड़ने की स्थिति को देखते-देखते वल्लभभाई पटेल का मन अहिसा से ऊबने लगा था। गाधी जी एक महान नेता थे। भारत जैसे सोए हुए तथा खण्ड-खण्ड देश को अखण्ड राष्ट्र के रूप मे खडा करने मे नि सन्देह गाधी जी की भूमिका ने धुरी की तरह काम किया था। वल्लभभाई पटेल हिन्दुस्तान मे आई पूरी जागृति तथा परिवर्तन का श्रेय महात्मा गांधी को देते थे, परन्तु अब जो परिस्थितिया बनने लगी थी, उनसे उनके कान खडे हो गए थे।

देश की आजादी को अग्रेज टालते जा रहे और अल्पसख्यको की समस्या उठाकर देश को विभाजन की ओर धकेल रहे थे। मुस्लिमलीग भारत राष्ट्र के शत्रु की भूमिका अदा कर रही थी।

जो दो बिल्लियों को लडाकर दोनो का हिस्सा हडप गया था। परन्तु हम बिल्ली नही है, हमारे होते सरकार के ये मनसूबे कभी पूरे नही होगे।''

मुस्लिमलीग और देशी राजा दोनो के प्रति सरदार पटेल का दृष्टिकोण साफ होता चला गया था। वे समझ गए थे कि ये दोनो ही भारत की आजादी मे रोडा अटकाने वाली समस्याएं पैदा कर रहे है। अत वे इनके प्रति अत्यधिक कठोर और सावधान हो गए।

विश्वयुद्ध मे दोनो महाशक्तियो मे से किसी के प्रति भी सरदार पटेल के मन मे सहानुभूति न थी। गाधी जी की सहानुभूति तो ब्रिटेन व फ्रास के साथ थी। गाधी जी कह चुके थे कि वे नाजीवादी ताकतो की हार तथा ब्रिटेन व फ्रास की विजय देखना चाहते है, परन्तु सरदार पटेल ने साफ-साफ कह दिया, ''ब्रिटिश साम्राज्य और जर्मन नाजीवाद इन दोनों में से हिन्दुस्तान किसी को भी पसन्द नही करता। साम्राज्यवाद की मदद करके नाजीवाद का नाश करने मे सहायता कीजिए, तो हम यह कहेगे कि ऐसी हालत मे तुम दोनों ही लडकर मर जाओ।''

सरदार पटेल सुभाषचन्द्र बोस की तरह अग्रेजो की कमजोरी पर प्रहार कर झटके से आजादी छीन लेने के पक्ष मे भी न थे। उनका विचार था कि अग्रेजो की कमजोरी हमारी स्वाधीनता का आधार नही है। हमे अपनी कमजोरिया मिटानी है। अपने-आपको इतना मजबूत बनाना है कि हम आजादी ले सके और उसे सम्भाल सके।

हा, देश की एकता एव अखण्डता की चिन्ता उन्हे खाए जा रही थी। वे लम्बे समय से स्वाधीनता आन्दोलन से जुडे थे और यह देखकर दु खी होने लगते थे कि सब लोग एकजुट होकर आजादी

की माग क्यो नही करते। जब सारे भारत का एकमात्र उद्देश्य अंग्रेजो को देश से बाहर करना और देश का आजाद करना है तो छोटे-छोटे स्वार्थो और मतभेदो को भुलाकर सब लोग एक महाशक्ति बनकर क्यो नही खडे होते?

पटेल देश की आजादी के बारे मे पूरी तरह आशावादी थे। जिस प्रकार आजादी के पौधे को रोपकर उसे पल्लवित और पुष्पित करने के लिए वे जीवनभर सघर्ष करते आए थे और उनके देखते-देखते सोया हुआ देश जागा था और सकल्पित होकर उठ खडा था, उससे वे पूरी तरह आशान्वित थे कि अंग्रेजो को हिन्दुस्तान से जाना ही पडेगा, हिन्दुस्तान को सदा के लिए गुलाम बनाकर नही रखा जा सकता।

गाधी जी के प्रति सम्पूर्ण समर्पण और उनके सिद्धान्तो व विचारो मे समूची आस्था के मामले मे सरदार पटेल सबसे आगे थे। परन्तु द्वितीय विश्वयुद्ध के दिनों तक पहुचते-पहुचते अहिसा के प्रति विश्व की महाशक्तियो का रुख तथा मुस्लिमलीग की अवसरवादिता तथा हिसा द्वारा पूरे हिन्दू समुदाय पर भारी पडने की स्थिति को देखते-देखते वल्लभभाई पटेल का मन अहिसा से ऊबने लगा था। गाधी जी एक महान नेता थे। भारत जैसे सोए हुए तथा खण्ड-खण्ड देश को अखण्ड राष्ट्र के रूप मे खडा करने मे नि सन्देह गाधी जी की भूमिका ने धुरी की तरह काम किया था। वल्लभभाई पटेल हिन्दुस्तान मे आई पूरी जागृति तथा परिवर्तन का श्रेय महात्मा गाधी को देते थे, परन्तु अब जो परिस्थितिया बनने लगी थी, उनसे उनके कान खडे हो गए थे।

देश की आजादी को अग्रेज टालते जा रहे और अल्पसख्यको की समस्या उठाकर देश को विभाजन की ओर धकेल रहे थे। मुस्लिमलीग भारत राष्ट्र के शत्रु की भूमिका अदा कर रही थी।

उसे इतनी चिन्ता हिन्दुस्तान के आजाद होने की नही थी, जितनी कि अपने लिए एक अलग मुस्लिम राज्य बनाने की थी। भाषा, धर्म और सस्कृति के नाम पर मुस्लिमलीग मुसलमानो को बहका रही थी और उन्हे भारत के टुकडे कर अलग मुस्लिम देश का स्वप्न दिखा रही थी। अग्रेज इस वात को समझ गए थे और गाधी जी की अहिसा के सिद्धान्तो पर ली गई समस्त उपलब्धियो को मुस्लिमलीग तथा ब्रिटिश सरकार दोनो ही नष्ट हुआ देखना चाहते थे। ऐसे मे उसी अहिसा के बल पर पूरे देश को खडा करके इतनी बडी चुनौतियो से नही जूझा जा सकता था। इस सत्य को पटेल समझ गए थे और उन्होने कुछ मामलो मे अहिसा के सिद्धान्तो से हटकर 'जैसे को तैसा' के सिद्धान्त पर चलने का मन बना लिया था। सुभाषचन्द्र बोस सरीखे नेता तो बहुत पहले ही अहिसा से अपना मोह भग कर चुके थे। जवाहरलाल नेहरू भी उखडने लगे थे।

उधर गांधी जी अहिसा के सिद्धान्त के प्रति इतने समर्पित थे कि वे किसी भी हालत मे हिसा का विचार तक स्वीकार नही कर सकते थे। काग्रेस का यह बहुत बडा दुर्भाग्य था कि उसके शीर्ष नेता तथा सचालक से उसके अनुयाइयो का मतभेद होने लगा था, परन्तु विषम परिस्थितियो मे भी गांधी जी सैद्धान्तिक परिवर्तन के लिए तैयार न थे। गाधी जी की इस सैद्धान्तिक जिद ने कई नुकसान कर दिए थे और कई और होने वाले थे। देश के महान नेता सुभाषचन्द्र बोस से गाधी जी का मतभेद अहिसा को लेकर ही हुआ। सुभाषचन्द्र बोस अकेले ऐसे नेता नही थे, जो गाधी जी की अहिसा से तग आ चुके थे, बल्कि काग्रेस मे सुभाषचन्द्र बोस के विचारो के अनुयायी इतने अधिक थे कि उन्होने गाधी जी की चुनौती के बावजूद बोस ने दूसरी बार अपने विचारो व नीतियो के

बल पर कांग्रेस अध्यक्ष पद जीतकर दिखाया था।

परन्तु गाधी जी अहिंसामूलक विचारो की हार को तैयार न थे और उन्हे कांग्रेस को अहिंसा के मार्ग पर ही चलाने की ऐसी धुन सवार हुई कि उन्होने कांग्रेस से अलग हो जाने की धमकी देकर सारे कांग्रेसियो का रुख अपनी ओर मोड लिया और सुभाषचन्द्र बोस के प्रयासो को बिल्कुल व्यर्थ कर दिया जिनके द्वारा वे कांग्रेस को अहिसा के समझौतावादी व अतिमानवतावादी दर्शन से निकालकर अपने देश मे अग्रेजो की हिसा का जवाब हिसा से देना चाहते थे। गाधी जी की जिद के सामने सुभाषचन्द्र बोस ने हार मान ली और वे कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर एक ओर हट गए। परन्तु गाधी जी इतने से ही शान्त नही हुए। उन्होने कांग्रेस को खुले शब्दो मे कह डाला, "कांग्रेस ऐसी घोषणा करे कि हिसा से पूरी तरह परहेज़ करेगी। कांग्रेस सकल्प ले कि स्वतन्त्र भारत मे हिसा का कोई स्थान नही रहेगा और बाहरी आक्रमण से देश की रक्षा के लिए भी सेना का प्रयोग नही किया जाएगा।"

गाधी जी की इस घोषणा से पटेल आदि सभी वरिष्ठ नेताओ ने यह फैसला लिया कि गाधी जी महामानव है, उनके सिद्धान्त कांग्रेस के सिद्धान्तो व उद्देश्यो से बहुत ऊचे है। अतः उन्हे अब कांग्रेस नेतृत्व के उत्तरदायित्व से मुक्त किया जाए, जिससे वे अपने विचारो व सिद्धान्तो के अनुसार अपने महान आदर्शो का रास्ता मुक्त रूप से तैयार कर सके।

इस फैसले को कार्यसमिति मे अन्तिम रूप दिया गया तथा गाधी जी इस दायित्व से मुक्त कर दिए गए। गाधी जी भी यही चाहते थे, अत कोई विवाद नही हुआ, कोई तनाव उत्पन्न नही हुआ। कांग्रेस परिस्थिति तथा चुनौतियो के अनुरूप अपनी रणनीति बनाने के लिए स्वतन्त्र हो गई।

अब कांग्रेस पर वल्लभभाई पटेल की पकड सबसे अधिक थी। वे व्यावहारिक ढग से सोचते थे, वे पूर्वाग्रहो से पूरी तरह मुक्त खुली हवा मे सोचने के आदी थे। गाधी जी को मुक्ति देकर समयानुकूल कांग्रेस को चलाने का दायित्व लेकर सरदार पटेल अत्यधिक सन्तुष्ट व खुश थे। अव उन्होने गिन-गिनकर एक-एक स्थिति से निबटने का फैसला कर लिया।

देश मे हिसा के बढते दौर को देखते हुए उन्होंने कहा, "समाज पर अत्याचार करने वालो के साथ आवश्यक हिसा इस्तेमाल किए बिना काम चला सकना मेरी बुद्धि के बाहर है।"

मुस्लिमलीग द्वारा आयोजित दगो का मुकाबला जब हिन्दू नही कर सके तो उन्हे लगा कि अहिसा ने लोगो को कायर बना दिया है। इस बात से उन्हे बहुत दु ख हुआ और उन्होने साफ कह दिया कि उन लोगो के प्रति अहिसा के पालन की आवश्यकता नहीं है, जो हथियार लेकर तुम्हे कत्ल करने निकले हो या तुम्हारा विनाश चाहते हो।

कांग्रेस ने सशर्त विश्वयुद्ध मे सहयोग करना स्वीकार कर लिया था। लेकिन ब्रिटिश सरकार सहमत नही हुई इस पर कांग्रेस ने फिर से विचार किया और सितम्बर, 1940 मे पं० जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस महासमिति के सम्मेलन मे गाधी जी के नेतृत्व मे कांग्रेस द्वारा असहयोग आन्दोलन छेडने का प्रस्ताव रखा। सरदार पटेल ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया और प्रस्ताव पारित हो गया। आन्दोलन का उद्देश्य भारत को युद्ध मे शामिल करने के सरकार के निर्णय का विरोध करना था।

गाधी जी ने युद्ध विरोधी भाषण देने के लिए सबसे पहले विनोबा भावे को चुना। विनोबा ने पवनार आश्रम में 17 अक्टूबर को युद्ध विरोधी भाषण देकर सरकारी कानून का उल्लघन किया।

18 नवम्बर को युद्ध विरोधी भाषण देकर गिरफ्तारी देने के लिए वल्लभभाई पटेल को चुना गया था। उन्हे साय 6 बजे अहमदाबाद की एक विशाल सभा मे भाषण देकर कानून भग करना था। परन्तु सरकार ने भारत रक्षा कानून की धारा 129 लगाकर सरदार पटेल को 17 नवम्बर को ही गिरफ्तार कर लिया। उस समय उन्हे 104 डिग्री बुखार था। उन्हे यरवदा जेल ले जाया गया। जेल मे उनका स्वास्थ्य लगातार गिरता गया और तग आकर सरकार ने उन्हे 20 अगस्त, 1941 को जेल से रिहा कर दिया।

अप्रैल, 1941 मे अहमदाबाद मे भीषण हिन्दू-मुस्लिम दगे हुए थे। इन दगो मे हिन्दुओ को भारी हानि उठानी पडी। इस समय सरदार पटेल यरवदा जेल मे थे। इन दगो मे हिन्दू इतने डर गए थे कि मुस्लिम बस्तियो को छोडकर भागे और दूसरी बस्तियों मे जाकर बस गए। सरदार पटेल को इन दगो से बहुत कष्ट हुआ। जेल से रिहा होने के बाद अहमदाबाद मे कार्यकर्त्ताओ की एक सभा को सम्बोधित करते हुए पटेल ने भरे कण्ठ से कहा, "मैने अपनी आखो से देखा है, उस समय का अहमदाबाद आज नही है। यहा जो दंगे हुए, उनमे केवल निर्दोष मनुष्य ही मारे गए। लोगो की सम्पत्ति नष्ट हुई, उससे भी ज्यादा दु ख मुझे इस बात का है कि हमारी इज्जत चली गई।"

दु खी जनता को सात्वना देते हुए उन्होने कडे शब्दो मे कहा, "भविष्य मे कभी भागना मत, हिम्मत से मुकाबला करना, सारी दुनिया ऐसा ही करती है . .हिन्दू हो या मुसलमान, छाती खोलकर मरो, परन्तु अहिसा का बहाना मत ढूढो। इन उपद्रवो मे अहिसा का नामोनिशान भी नही था। अहिसा कायरता को ढकने का वस्त्र नही है।"

सरदार पटेल रिहा हो चुके थे, परन्तु प० जवाहरलाल नेहरू अभी तक जेल मे थे उन्हे उत्तरी भारत मे युद्ध विरोधी भाषण देने के लिए गिरफ्तार किया जा चुका था। कांग्रेस के अनेक नेता जेल मे थे, परन्तु आन्दोलन जारी था।

23 मार्च, 1942 को क्रिप्स मिशन लेकर सर स्टेफोर्ड क्रिप्स भारत पहुचे।

उन्होने वल्लभभाई पटेल तथा अन्य प्रमुख कांग्रेसी नेताओ से दिल्ली मे बातचीत की और ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजे गए प्रस्ताव उनके समक्ष रखे। परन्तु इन प्रस्तावो मे भी पूरी स्वाधीनता के स्थान पर औपनिवेशिक दर्जा देने की बात घुमा-फिराकर कही गई थी।

कांग्रेस ने क्रिप्स मिशन को पूरी तरह अस्वीकार कर दिया। क्रिप्स मिशन पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सरदार पटेल ने कांग्रेस कार्यसमिति में स्पष्ट घोषणा कर दी कि अब समय आ गया है कि अंग्रेजो से भारत छोड़ने को कहा जाए। उन्होने इस आशय का प्रस्ताव भी समिति के समक्ष रख दिया। जवाहरलाल नेहरू जी तब तक रिहा हो गए थे और उस समिति की बैठक मे मौजूद थे। नेहरू तथा मौलाना आजाद ने उस दिन इस प्रस्ताव को जल्दबाजी मे उठाया गया कदम माना और अधिक उत्साह नही दिखाया।

अप्रैल, 1942 मे प्रयाग मे कांग्रेस कार्यसमिति तथा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठके हुई। इन बैठको मे महात्मा गाधी का सन्देश पढकर सुनाया गया, सन्देश मे लिखा था, "ब्रिटिश सरकार का यह कहना कि वह भारत मे अल्पसख्यको तथा देशी राज्यो की रक्षा के लिए है, एक धोखा है। क्योकि ये दोनो उसके ही बनाए हुए है। ब्रिटेन भारत की रक्षा करने के अयोग्य है।

अतएव उसे यहा से हट जाना चाहिए। यदि ब्रिटेन यहा से हट जाए तो हम जापान से यहा न आने को कहेगे और यदि जापान फिर भी भारत मे आएगा तो हम उसके साथ असहयोग करेगे।"

गाधी जी अब 'अग्रेजो भारत छोडो' आन्दोलन पर दृढ हो गए। जुलाई मे वर्धा मे कार्यसमिति की बैठक बुलाई गई, जिसमे कई दिन की बहस के बाद यह प्रस्ताव पारित हो गया। 2 अगस्त, 1942 को प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय पटेल ने लम्बा भाषण दिया और अन्त मे कहा, "दूसरा कोई मार्ग ही नही है, हमे आजाद होना है। गुलामी अब एक क्षण भी बर्दाश्त नही हो सकती।"

इस अवसर पर महात्मा गाधी ने भी स्पष्ट शब्दों मे कहा, "अब कोई समझौता नही, कोई बीच का मार्ग नही। हमे पूरी आजादी चाहिए, अग्रेज वापस जाए।"

इस प्रस्ताव के पारित होते ही पूरे देश मे खलबली मच गई। जनता अपने नेताओ का तन-मन-धन से साथ देने के लिए अन्तिम लडाई मे कूदने को तैयार हो गई। ब्रिटिश सरकार घबरा गई। गाधी जी जैसे विनम्र और सहनशील व्यक्ति द्वारा 'अग्रेजो भारत छोडो' कहा जाना अग्रेजो को असह्य था। परन्तु भारतीय जनता पता नहीं कब से इस घडी का इन्तजार कर रही थी।

सुभाषचन्द्र बोस अग्रेजो के खिलाफ खुली लडाई लडने के उद्देश्य से भारत छोडकर जर्मनी पहुच चुके थे और वहां जापान के सहयोग से भारत पर हमला करके देश को आजाद कराने की योजना पर काम कर रहे थे।

ब्रिटिश सरकार को सुभाष के बारे मे पूर्ण जानकारी थी। उधर युद्ध मे जापान हावी था, जर्मनी आगे बढता जा रहा था। ऐसे मे कांग्रेस का सम्पूर्ण असहयोग, समूचे देश का असहयोग था। जापान के भारत पर हमले की सम्भावना के समय भारत का

ब्रिटिश सरकार से खुला असहयोग करना और अंग्रेजो से तुरन्त भारत छोडने को कहना बहुत गम्भीर बात थी। एक ऐसी बात जिसे ब्रिटेन किसी कीमत पर स्वीकार करने को तैयार न था।

तुरन्त योजना बनी और दमनचक्र शुरू हो गया। पहले ही दौर मे गाधी जी व सरदार पटेल तथा काग्रेस कार्यसमिति के 14 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया। 8 अगस्त की रात को बम्बई पुलिस ने गाधी जी तथा सरदार पटेल को गिरफ्तार किया तथा 9 अगस्त प्रातः 4 बजे कार्यसमिति के सदस्य गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तारियो का दौर इतना व्यापक था कि अकेले बम्बई शहर में 150 से अधिक काग्रेस कार्यकर्त्ता गिरफ्तार किए गए। पूरे भारत मे 9 अगस्त को ही कई हजार गिरफ्तारिया हुई।

जनता अपने नेताओ की गिरफ्तारी का समाचार सुनकर इतनी उग्र हो गई कि उसने रेल की पटरिया उखाडना, तार काटना, डाकखानो, थानों आदि सरकारी इमारतो को आग लगाना आरम्भ कर दिया। अग्रेजो भारत छोडो आन्दोलन नेताओ की अनुपस्थिति मे जनता ने अपने हाथ मे ले लिया। नगर ही नही गावो की जनता भी इस आन्दोलन मे कूद पडी।

छात्रों ने स्कूल व कॉलेज छोड दिए, मज़दूर भी मैदान मे कूद पडे। छात्रो ने पूरे देश मे कहर ढा दिया। पुलिस के साथ सघर्ष मे बडी सख्या मे छात्र घायल हुए और अनेक लोगो की जान गई। गावो मे लोगो पर पुलिस व सेना ने भारी अत्याचार किए। बलात्कार, लूट, मार-काट और घरो मे आग लगाने से लेकर भीषण यातनाए देने तक पता नही क्या-क्या लोगो को सहना पडा। नगरो मे पुलिस ने लोगो पर लाठी-चार्ज व अश्रुगैस आदि तरीको से काबू करने के अत्याधिक प्रयास किए। अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी की एक

रिपोर्ट के अनुसार 2,15,000 से भी अधिक भारतवासियो ने इस आन्दोलन मे अपनी जाने गवाई।

अन्तरिम सरकार तथा भारत विभाजन

15 जून, 1945 को सरदार पटेल तथा कांग्रेस कार्यसमिति के अन्य सभी सदस्यो को जेल से रिहा कर दिया गया। महात्मा गाधी को बीमारी के कारण पहले ही रिहा किया जा चुका था।

इस बीच दुनिया के इतिहास मे भारी फेरबदल हो चुका था। विश्व पटल पर कई महत्त्वपूर्ण घटनाएं घट चुकी थी।

21 अक्टूबर, 1943 को सुभाषचन्द्र बोस जापान मे भारत की अन्तरिम सरकार की घोषणा कर चुके थे। जिसका नाम था 'आजाद हिन्द सरकार'। जापान, जर्मनी, इटली, क्रोएशिया, फिलीपीस, थाइलैंड, वर्मा आदि देश इस सरकार को मान्यता प्रदान कर चुके थे। 24 अक्टूबर, 1943 को आजाद हिन्द सरकार ने ब्रिटेन और अमरीका के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी थी और वह भारत पर हमला कर काफी इलाका जीतने के बाद भारत की ब्रिटिश सरकार को चुनौती दे रही थी कि इसी समय जर्मनी पर मित्र राष्ट्रो ने शिकजा कस दिया। हिटलर ने आत्महत्या कर ली और जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया।

6 अगस्त को अमरीका ने जापान के नगर हिरोशिमा पर और 9 अगस्त को नागासाकी पर परमाणु बम गिरा दिया। जापान की कमर टूट गई और उसने आत्मसमर्पण कर दिया।

जर्मनी और जापान के पतन से सुभाषचन्द्र बोस का 'आजाद हिद फौज' अभियान सफल नही हो आया और उसे पराजय का मुह देखना पडा। सुभाषचन्द्र बोस एक विमान दुर्घटना मे मारे गए।

इन परिस्थितियों में भारत की दशा अनाथ और बधुवा बालक जैसी हो गई, जिसे पकडे रखने मे ब्रिटेन गर्व का अनुभव करने लगा था।

द्वितीय विश्वयुद्ध समाप्त हो चुका था और वह ब्रिटेन को विजेता बना गया था। अब उसे भारत के नेताओं से बात करने की न इच्छा थी, न जल्दी।

भारत के हाथ से एक मौका निकल चुका था। 1942 के 'भारत छोडो आन्दोलन' को अग्रेजो ने पूरी तरह कुचल दिया था, सुभाषचन्द्र बोस का 'दिल्ली चलो' का अभियान मौत के घाट उतार दिया गया था। भारतीय नेताओ मे मायूसी का माहौल था। जनता आग से खेलकर उसकी भारी कीमत चुकाने के बाद भी कुछ हासिल नही कर पाई थी।

गाधी जी को फिर से काग्रेस का नेतृत्व सौपना और गाधी जी का 'अग्रेजो भारत छोडो' आन्दोलन निरर्थक लगने लगा था। कही भी खुशी की कोई किरण न थी।

हा भारत का एक तबका बेहद प्रसन्न था। यह था जिन्ना के नेतृत्व मे 'मुस्लिमलीग'। देश की रीढ मे छुरा धोपने का काम करता हुआ, गाधी जी तथा उनके आन्दोलन की खिल्ली उडाता हुआ मुस्लिमलीग अहिसावादियो की नई शैली को एक और मूर्खता कहकर फूले नही समा रही थी। भारत की आजादी मे लम्बे समय तक अडगा डालने वाला तथा काग्रेस के मनसूबो को खुली चुनौती देने वाले इस समूह ने अग्रेजो से हाथ मिलाया था। अग्रेजो को इसने आगाह कर रखा था कि वे काग्रेस की चालो मे न आए। इतना ही नही, काग्रेस की कमजोरियो को उजागर करने तथा काग्रेस के कमजोर वर्ग पर प्रहार करने की रीतिया तक यह समूह अग्रेजो को बताता रहा था। इसीलिए ब्रिटिश सरकार यह समझ

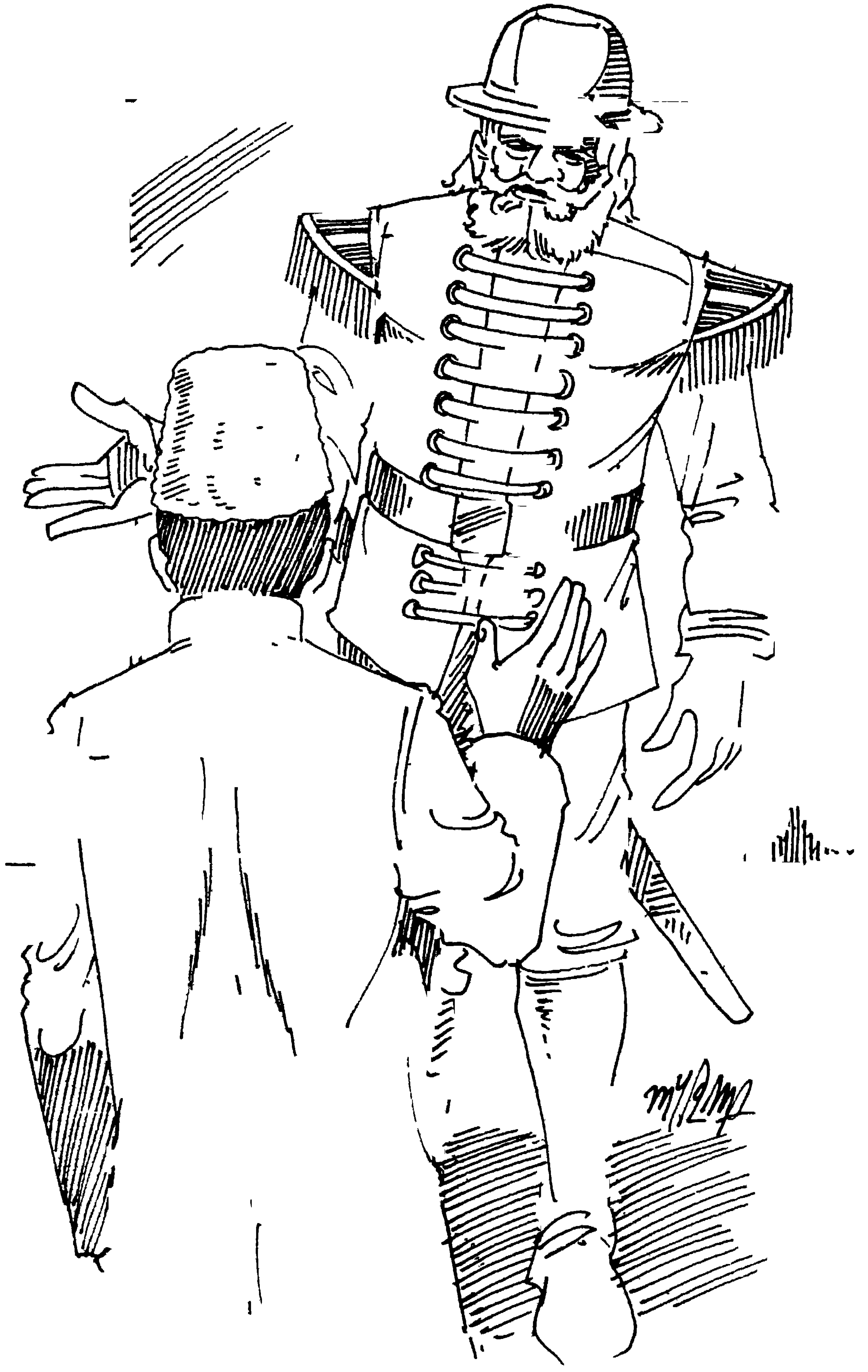

पाई थी कि भारतीय समाज की साम्प्रदायिक विलगता उनका सबसे बडा हथियार है। इस कमजोरी के होते कांग्रेस कितने ही आन्दोलन कर ले, ब्रिटिश सरकार से जीत नही पाएगी।

कांग्रेस भी इस सत्य को अच्छी तरह समझ गई थी कि मुस्लिमलीगियो की काली करतूते उसके मार्ग की सबसे बड़ी बाधाए है। अत. कांग्रेस ने अपनी रणनीति को अल्पसंख्यक हितों से जोडने का पूरा प्रयास किया और मुसलमानो को कांग्रेस से जोड़ने तथा जिन्ना को मनाकर राष्ट्रीय एकता स्थापित करने जैसे अनेक कदम उठाए गए, परन्तु जिन्ना नही माना। वह पाकिस्तान की धोषणा कर चुका था और हर कीमत पर पाकिस्तान चाहता था।

गाधी जी अब बुरी तरह चिन्तित हो उठे थे। जिन्ना ने अपनी मागें इतनी बढा ली थी कि उन्हें माना नही जा सकता था। ब्रिटेन की सरकार हिन्दुस्तान को आजादी देने के नाम पर कई शर्ते रख रही थी, जिसमे सबसे खतरनाक और असम्भव शर्त थी अल्पसंख्यको के साथ समझौता। गाधी जी इतने उदार थे कि वे अल्पसख्यको को महत्त्व देने मे सीमा से बहुत आगे जा सकते थे। अतः पटेल तथा नेहरू जैसे वरिष्ठ नेता तथा कांग्रेस कार्यसमिति इस मामले में पूरी तरह सतर्क हो गई थी।

पटेल विश्व की धटनाओं तथा ब्रिटेन के अन्दरूनी हालात पर विशेष रूप से नजर रखे हुए थे। जो कुछ धटित हो रहा था, उससे एक बात साफतौर पर उभरकर सामने आ गई थी कि युद्ध मे विजयी होने के बावजूद ब्रिटेन अन्दर से खोखला हो उठा है। अब और लड़ाई लडने तथा आन्दोलनो की मार झेलने की क्षमता और इच्छाशक्ति वह तेजी से खोने लगा था। औपनिवेशिक शासन समाप्ति की ओर था क्योकि द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद हर देश मे

जन-चेतना उभर आई थी और अब किसी भी देश की जनता गुलाम रहने को तैयार न थी।

पटेल की दृष्टि मे भारत के सामने इस समय आजादी लेना इतनी बडी समस्या नही थी जितनी कि साम्प्रदायिकता की समस्या, जिसे मुस्लिमलीग बढा रही थी। ऐसे मे पटेल इस निष्कर्ष पर पहुचे कि किसी प्रकार सत्ता मे आया जाए फिर साम्प्रदायिक समस्या से निबटना और अग्रेजो से आजादी लेना आसान हो जाएगा। एक सम्भावना यह भी लग रही थी कि चुनी हुई आन्तरिक सरकार मे मुस्लिमलीग के साथ काम करके तो देखे, हो सकता है, मुस्लिमलीगियो का मन बदल जाए और देश विभाजन से बच जाए और भारत शीघ्र आज़ाद हो जाए। सब लोग इससे सहमत थे, अत. आगे की रणनीति पर अमल का निश्चय कर लिया गया।

वायसराय से मुलाकात कर गाधी जी ने चुनाव कराने का फैसला करा लिया। कांग्रेस और मुस्लिमलीग दोनो मे चुनाव कराने तथा अन्तरिम सरकार बनाने के मुद्दे पर सहमति हो गई।

25 जून को शिमला में वायसराय की अनुमति से एक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। जिन्ना के उग्र वक्तव्यो के कारण शिमला आयोजन बिना कोई ठोस निर्णय लिए समाप्त हो गया।

फिर एक महाशून्य उभर आया। आपसी असहमति तथा मतभेदो के कारण देश की आजादी अधर मे लटकी रह गई।

सौभाग्य से जुलाई, 1945 मे ब्रिटेन मे चुनाव हुए और सत्ता मजदूर दल के हाथ मे आ गई। ब्रिटेन के सबसे अधिक भारत विरोधी प्रधानमन्त्री चर्चिल को जाना पडा, उनके स्थान पर एटली नए प्रधानमन्त्री बने। भारत के प्रति कट्टर रुख रखने वाले मिस्टर एमरी के स्थान पर लॉर्ड पैथिक लॉरेन्स भारत मन्त्री बने। अब

भारत को नई आशाए बध गई।

21 अगस्त को भारत मन्त्री ने ब्रिटेन के प्रधानमन्त्री के उदार रुख पर यह घोषणा कर दी कि शीघ्र ही भारत मे केन्द्रीय एसेम्बली व प्रान्तीय एसेम्बलियो के चुनाव कराए जाएगे।

पटेल ने चुनाव प्रचार की बागडोर अपने हाथ मे ले ली और रात-दिन देशभर मे घूम-घूमकर कांग्रेस के अनुकूल वातावरण बनाने मे जुट गए। उनके अन्य सहयोगी थे मौलाना आजाद, राजगोपालचार्य, रफी अहमद किदवई, डॉक्टर राजेन्द्रप्रसाद, गोपाल रेड्डी, मौलाना बख्श तथा कामराज।

चुनाव हुए और केन्द्रीय एसेम्बली मे कांग्रेस को 57 स्थान तथा मुस्लिमलीग को 30 स्थान मिले। प्रान्तीय एसेम्बलियो मे कांग्रेस को 923 स्थान प्राप्त हुए तथा मुस्लिमलीग को 425 स्थान मिले।

चुनावो के नतीजो ने कांग्रेस को पीछे धकेल दिया और मुस्लिमलीग ने भारी बढत दर्ज कर जिन्ना को मुसलमानो के लोकप्रिय तथा सर्वमान्य नेता के रूप में स्थापित कर दिया। कांग्रेस और मुस्लिमलीग के बीच की खाई और चौडी हो गई। सरकार बनाने पर समझौते के आसार धूमिल होने लगे।

23 मार्च, 1946 को ब्रिटेन ने एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा, जिसका उद्देश्य कांग्रेस तथा मुस्लिमलीग के बीच सुलह-समझौता कराने के बाद भारत मे अन्तरिम सरकार का गठन करवाना तथा भारतीय समस्याओ पर खुलकर विचार करना था। भारतीय समस्या को हल करने के लिए इस मिशन को ब्रिटेन ने अपना अन्तिम प्रयास बताया।

सरदार वल्लभभाई पटेल इस समय महात्मा गाधी और कांग्रेस पार्टी से भी बहुत आगे जाकर इस प्रयत्न मे लग गए कि लीग के

प्रभाव को कम करके कांग्रेस का वर्चस्व ब्रिटेन की दृष्टि मे स्थापित कर सके और मुसलमानो को कांग्रेस से जोडे। गांधी जी ने उन्हे सावधान किया कि उन पर मुस्लिमलीग के अति विरोध के कारण मुस्लिम विरोधी आरोप लगने लगे है, अत: वे सावधानी बरते, परन्तु पटेल ने गांधी जी की हिदायतो की परवाह नही की।

12 मई, 1946 को कैबिनेट मिशन ने अपनी वार्ता समाप्त कर दी और वह इस नतीजे पर पहुची कि लीग अन्तरिम सरकार मे कांग्रेस के बराबर प्रतिनिधित्व चाहती है। कांग्रेस के पाच, मुस्लिमलीग के पांच तथा अन्य दलो के दो प्रतिनिधि अन्तरिम सरकार मे शामिल हो तो मुस्लिमलीग अन्तरिम सरकार में शामिल होने को तैयार है।

भारी विचार-विमर्श के बाद वायसराय ने अन्तरिम सरकार के गठन की व्यवस्था दी। इस व्यवस्था के अनुसार इस सरकार मे कुल 14 सदस्यो का प्रावधान किया गया था, जिसमे कांग्रेस के 6, मुस्लिमलीग के 5, सिखो का 1, ईसाइयों का 1 तथा पारसियो का 1 प्रतिनिधि होगा।

2 सितम्बर, 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व मे अन्तरिम सरकार ने शपथ ली, जिसमे सरदार पटेल गृहमन्त्री बने। इसके अतिरिक्त डॉक्टर राजेन्द्रप्रसाद, जगजीवनराम, राजगोपालाचार्य, आसफअली, जॉन मथाई, सरदार बलदेवसिह, सर शफात अहमद खा, सैयद अली जहीर तथा सी. एच. भाभा इस सरकार मे शामिल हुए।

25 अक्टूबर को मुस्लिमलीग भी सरकार मे शामिल हो गई। लीग की रग-रग में शरारत और शैतनी फितरत भरी थी। मुस्लिमलीग ने सरकार के अन्दर रहकर पाकिस्तान के लिए सघर्ष करना अपना ध्येय बताया।

15 अक्टूबर को मुस्लिमलीग खुलेआम नौआखाली और त्रिपुरा मे भीषण हिन्दू-मुस्लिम दगे करा चुकी थी, जिसमे वडे पैमाने पर हिन्दू स्त्रियो के साथ बलात्कार किए गए, सम्पत्ति लूटी गई, हत्याए की गई तथा हिन्दुओ को बलपूर्वक मुसलमान बनाया गया।

सरदार पटेल मुस्लिमलीग की इन हरकतो के लिए ब्रिटिश सरकार को जिम्मेदार मानते थे। देश को आजादी देने मे देर करने का बहाना तलाशने के लिए अग्रेजी सरकार मुस्लिमलीगियो को दगे करने के लिए भड़का रही थी और पाकिस्तान बनाने तथा हिन्दुस्तान का अधिक-से-अधिक भू-भाग मुसलमानो के लिए अलग देश बनाने के नाम पर हथिया लेने के उद्देश्य से मुस्लिमलीगी हिन्दुओ पर अत्याचार करने मे लगे थे।

पटेल का आरोप था कि सरकारी अधिकारी मुस्लिमलीग के साथ है और मुस्लिमलीग पीछे से छुरा घोपकर पाकिस्तान लेना चाहती है। मुस्लिमलीगियो की धोखाधडी पर टिप्पणी करते हुए सरदार पटेल ने कहा, "जब तक लीग जहर उगलना बन्द नही करेगी, तब तक शान्ति नही हो सकती। सरकारी अफसर यदि पारदर्शिता से काम करना चाहते है तो ठीक है, नही तो उसका परिणाम बुरा होगा। मै आपसे अपील करता हू कि धोखे से पाकिस्तान लेने की बात मत करो, हा यदि तलवार से लेना है तो तलवारे निकाल लो, हम मुकाबले के लिए तैयार है।"

अन्तरिम सरकार में वित्तमन्त्री का पद मुस्लिमलीग के लियाकत अली खा के पास था। वे सरदार पटेल के साथ सदैव असहयोग करते थे। हिन्दुओ को नुकसान पहुचाने, मुसलमानों को लाभ पहुचाने तथा मुसलमानो को हिन्दुओ के खिलाफ भड़काने का कोई मौका मुस्लिमलीग के मन्त्री हाथ से नही जाने देते थे। प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू तो मुस्लिमलीगी मन्त्रियों के असहयोग से परेशान

थे ही, वल्लभभाई पटेल तो इतने दु:खी थे कि उनका जी करता था कि इन दुष्टो को इनकी दुष्टता की कठोर सजा दी जाए।

धीरे-धीरे यह असहयोग इतना बढ गया कि असह्य हो गया। सरदार पटेल ने वायसराय से हस्तक्षेप की माग की और धमकी दी कि यदि मुस्लिमलीगियो को सरकार से नही हटाया गया तो कांग्रेस त्यागपत्र दे देगी।

ज्यो-ज्यो समय आगे बढता गया, अन्तरिम सरकार दो गुटो मे विभाजित होती गई और मुस्लिमलीग पाकिस्तान निर्माण के लिए खुलकर प्रचार करने लगी। पूरा सरकारी प्रशासन मुस्लिम और गैर-मुस्लिम भागो मे बंट गया।

गृहमन्त्री के रूप में सरदार पटेल यह भी अनुभव कर रहे थे कि उनके अधिकार समिति है जबकि वायसराय और गवर्नर अपनी विशेष शक्तियो का बार-बार प्रयोग करते है।

बगाल में लीग ने दगे भडका दिए और सरकार कुछ न कर सकी। सरदार पटेल मार्शल लॉ लगाना चाहते थे, परन्तु वायसराय ने अनुमति नही दी। पूर्वी बगाल की प्रतिक्रिया में बिहार मे दगे भडक उठे और वहा से हिन्दुओं ने बगाल का बदला बिहार के मुसलमानो से लिया।

बिहार के साम्प्रदायिक दगो की न्यायिक जाच कराने के लिए जब गाधी जी ने बल दिया तो बिहार के गवर्नर और मन्त्रिमण्डल ने गाधी जी का अनुरोध ठुकरा दिया। गाधी जी को बहुत दु ख हुआ क्योंकि जांच की माग पटेल के कठोर रुख के कारण ठुकराई गई थी।

पटेल को गाधी जी की मुसलमानो के प्रति बढती सहानुभूति पर दुख होने लगा था, उनकी अहिसा नीति को अपना हथियार मानकर हिन्दू कायर हुए जा रहे थे और हिसा अपनाकर मुसलमान अहिसा की धज्जिया उडा रहे थे। फिर भी गाधी जी मुसलमानो के

प्रति सहानुभूति रखते थे, उनके कष्टो से दु खी होते थे। यह बात पटेल की समझ में नही आ रही थी। पटेल यह मानने लगे थे कि गाधी जी मुस्लिमलीगी नेताओ के प्रभाव में आ जाते है। वे जानते थे कि लीगियो के आसू नकली है और गाधी जी नर्म-दिल असली व नकली आंसुओ मे भेद करना नही जानते थे।

उधर पटेल ब्रिटेन की सरकार पर लगातार यह आरोप लगा रहे थे कि स्वतन्त्रता मे देरी करके ब्रिटेन सरकार भारत को दगो मे झोंक रही है।

भारतीय राजनीति में व्याप्त अस्थिरता जब सीमा पार करने लगी तो ब्रिटिश प्रधानमन्त्री एटली ने 20 फरवरी, 1947 को ब्रिटिश कॉमन सभा मे ऐतिहासिक घोषणा की कि जून, 1948 मे अंग्रेज भारत की सत्ता से अपने-आपको अलग कर लेगे और सत्ता भारतीयो के हाथो में सौंप दी जाएगी। साथ ही यह घोषणा भी की गई कि यदि भारतीय सविधान परिषद एक सर्वसम्मत से संविधान न बना सकी तो शासनाधिकार तत्कालीन केन्द्रीय सरकार अथवा सामान्य प्रान्तीय सरकारो अथवा किसी अन्य को देकर देशी रियासतो पर से भी ब्रिटिश राज्य का आधिपत्य समाप्त कर दिया जाएगा।

ब्रिटिश सरकार की इस घोषणा के साथ ही हिन्दुस्तान मे साम्प्रदायिक दगो का भयानक दौर शुरू हो गया। मुस्लिमलीग ने यह फैसला किया कि ज्यादा-से-ज्यादा प्रान्तों को अपने कब्जे मे लिया जाए, क्योकि सर्वसम्मत विधान तो बनने से रहा। मुस्लिमलीग सविधान निर्मात्री सभा मे शामिल तक नही है, ऐसी स्थिति मे अंग्रेज भारत से जाते-जाते प्रान्तीय सरकारो को ही सत्ता सौपने पर विवश होगे। बगाल और सिन्ध, सीमा प्रान्त को भी मुस्लिमलीग के कब्जे मे लेने के लिए लीगी अस्थिरता फैलाने लगे। सीमा प्रान्त मे

हिन्दुओ की सख्या कम थी तथा वहा काग्रेस का शासन था। परन्तु मुस्लिमलीग ने क्षेत्र के मुसलमानो को भड़काकर वहा हिन्दुओं और सिखो को तबाह करना शुरू कर दिया। परिणामतः हिन्दू और सिख वहा से भागने पर मजबूर हुए। सीमा प्रान्त के गर्वनर तथा अग्रेज अधिकारियो ने मुस्लिमलीग का साथ दिया। मुस्लिमलीग ने पंजाब को भी निशाना बनाया और वहा के मुसलमानो को हिन्दुओ व सिखो के विरुद्ध भडका दिया। पजाब के गवर्नर तथा अग्रेज़ अफसर भी मुस्लिमलीग के साथ हो गए। पजाव की सयुक्त सरकार मुख्यमन्त्री खिजर हयात खा गवर्नर व सरकार अफसरो के असहयोग तथा लीगियो के आतक से इतना डर गया कि उसने अपने पद से त्याग-पत्र दे दिया। मुस्लिमलीग यही चाहती थी। उसने तुरन्त अपना मन्त्रिमण्डल गठित कर पजाव पर कब्जा करने का प्रयास किया जो सफल न हो सका।

4 मार्च को लाहौर मे पजाब के सिखो व हिन्दुओ ने पाकिस्तान विरोधी प्रदर्शन किया, जिस पर मुसलमानो के जान-बूझकर हमले के कारण पूरे प्रान्त मे भीषण हिसा भड़क उठी।

4 मार्च तक पजाब मे 2,049 व्यक्ति मारे जा चुके थे तथा 1,103 भयंकर रूप से घायल हुए थे।

24 मार्च को लॉर्ड माउण्टबेटन ने लन्दन से दिल्ली पहुचकर भारत के वायसराय पद की शपथ ली और काग्रेस तथा मुस्लिमलीग के प्रतिनिधियो से अलग-अलग बातचीत के बाद यह निर्णय लिया कि मुसलमानों द्वारा की जा रही पाकिस्तान की माग को मान लिया जाए, क्योकि कांग्रेस तथा मुस्लिमलीग दोनो ही विभाजन को अनिवार्य मानते है।

पजाब तथा बगाल के विभाजन का फैसला लिया गया।

2 मई, 1947 को दिए गए माउण्टबेटन के फैसले को काग्रेस

तथा मुस्लिमलीग ने इसी शर्त पर स्वीकार किया कि भारत को पूर्ण सत्ता हस्तान्तरण कर दिया जाएगा। फलत पूर्ण सत्ता हस्तान्तरण की प्रक्रिया तत्काल आरम्भ कर दी गई। देश की स्थिति अब इतनी बिगड चुकी थी कि अग्रेज सत्ता हस्तान्तरण रोककर उसे और अधिक बिगडने देने अथवा स्वय सत्ता सम्भालने के पक्ष मे न थे।

2 जून, 1947 को लॉर्ड माउण्टबेटन ने भारत विभाजन की योजना को प्रकाशित किया तथा अगले ही दिन काग्रेस तथा मुस्लिमलीग ने इसे स्वीकार कर लिया। भारत के सभी समुदायो ने यह योजना स्वीकार कर ली और यह मान लिया कि दोनो सम्प्रदायो के लिए अलग-अलग देश बन जाने पर हिन्दू व मुसलमानो के बीच टकराव की समस्या हमेशा-हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी और देश आजाद हो जाएगा।

सरदार पटेल ने विभाजन स्वीकार करने को उचित ठहराते हुए कहा, "हमने हिन्दुस्तान के टुकडे किए जाना कबूल कर लिया। कई लोग कहते है कि हमने ऐसा क्यों किया और यह गलती थी। मै अभी तक नही मानता कि हमने कोई गलती की और मै यह भी मानता हू कि यदि हमने हिन्दुस्तान के दो टुकडे करना मजूर न किया होता तो आज जो हालत है, उससे भी बुरी हालत होने वाली थी, फिर हिन्दुस्तान के दो नही बल्कि अनेक टुकड़े हो जाने वाले थे ..अग्रेजो को हटाना लाजिमी था। उनके रहते हालात बेकाबू होते ही जाते, क्योकि वे मुस्लिमलीग को बराबर शह दे रहे थे। हालात काबू से बाहर होने लगे थे। इसीलिए हमे विभाजन स्वीकार करना पडा हम या तो विभाजन मानते या फिर हिन्दुस्तान अपने हाथो से जाने देते, यही स्थिति बन गई थी।"

महात्मा गाधी को देश विभाजन से बहुत दु ख हुआ। वे प्राय कहा करते थे कि पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा। परन्तु विषम

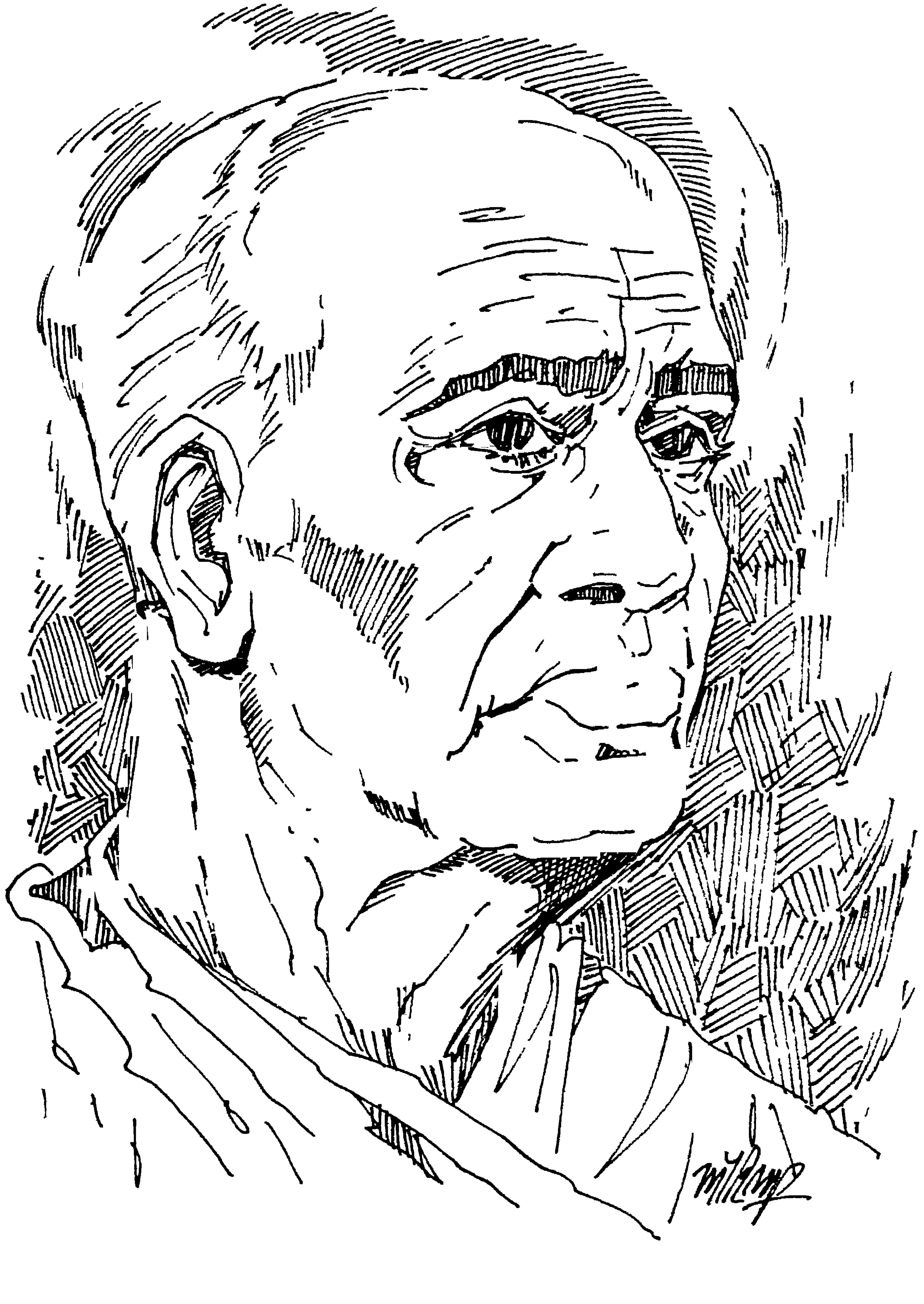

परिस्थितियों में गाधी जी ने भी भारी मन से इसे स्वीकार कर लिया।

पाकिस्तान स्वीकार करने के लिए जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल की पूरी देश मे कटु आलोचना हुई। पटेल बहुत दु खी थे, वे समझ नही पा रहे थे कि देश के लोगो को कैसे विश्वास मे लिया जाए कि जो कुछ हुआ है, वह एक विवशता थी। देश के लोगो को समझाते हुए उन्होने भरे गले से कहा, "मै जीवनभर भारत की अखण्डता के लिए प्रयत्नशील रहा हू। आप सबको इस प्रस्ताव से जो दु ख हुआ है, उससे कम मुझे नही हुआ है, परन्तु विश्वास कीजिए कि इसके अलावा कोई और चारा नहीं रहा था। इसीलिए मैने आगे बढकर कहा—ब्रिटिश सरकार हिन्दुस्तान का विनाश करने पर उतारू है, यदि यह सब उसी तरह चलता रहा जैसे कि चल रहा है तो मुझे निश्चित भय है कि समूचा भारत पाकिस्तान बन जाएगा। इसलिए यदि सारे भारत को पाकिस्तान बनने से बचाना हो तो इस प्रस्ताव को स्वीकार करके, विभाजन का खतरा उठाकर भी अग्रेज सरकार को भारत से हटाने मे ही हमारी बुद्धिमानी होगी। इसी मे देश का सुख निहित है। भविष्य की बहुत बडी बुराइयो को रोकने के लिए इस बुराई को स्वीकार करके अंग्रेजो के इस पाप को भारत से हमे विदा करना चाहिए। इस दृष्टि से मैं दु:ख और वेदना से रुदन करने वाले अपने मित्रों से अनुरोध करता हूं कि वे इस कडुवे घूट को पी जाए।"

दोनो देशो के समुचित बटवारे के लिए, उनके बीच सीमा रेखा खीचने के लिए विभाजन परिषद गठित कर दी गई, जिसकी पहली बैठक 27 जून को तथा अन्तिम 6 अगस्त, 1947 को हुई।

14 अगस्त, 1947 को पाकिस्तान की एक आजाद देश के रूप मे घोषणा की गई तथा 15 अगस्त, 1947 को शेष देश को

'भारत' नाम से स्वाधीन घोषित किया गया।

विभाजन परिषद ने 1 दिसम्बर, 1947 तक काम किया। भारत की ओर से परिषद मे पूरा दायित्व सरदार पटेल ने बडी सूझ-बूझ और बौद्धिक परिपक्वता के साथ निभाया।

विभाजन मे चल व अचल सम्पत्ति का विभाजन अत्यधिक कठिन काम था। चल सम्पत्ति का 80% भारत को तथा 20% पाकिस्तान को दिया गया। युद्ध के कारण ब्रिटेन ने भारत पर पाच बिलियन डॉलर का ऋण छोड़ा था। पाकिस्तान ने बडी मुश्किल से उस ऋण का 17.5% देना कबूल किया क्योकि उसे 17 5% नकदी दी गई थी। सरदार वल्लभभाई पटेल मुस्लिमलीग के धूर्त इरादो से परिचित थे, अत· वे नकदी के भुगतान को स्थगित रखना चाहते थे, जिससे कश्मीर में हो रहे युद्ध मे पाकिस्तान कमज़ोर बना रहे, परन्तु गाधी जी इसके विरोध मे उपवास पर बैठ गए और मन मारकर सरदार पटेल को अपना इरादा बदलना पड़ा।

गाधी जी की इस जिद का परिणाम भारत को बाद में भुगतना पडा। पाकिस्तान को नकदी का भुगतान होते ही उसने तुरन्त अपनी सेना दुरुस्त की, हथियार खरीदे और कबायलियो को कश्मीर में धकेलकर उसके एक हिस्से पर कब्जा कर लिया।

सरदार पटेल की कूटनीति के खिलाफ गाधी जी ने ज़िद तथा नेहरू जी की युद्धविराम की सलाह न की होती तो पाकिस्तान कश्मीर के इस हिस्से पर कब्जा करने मे सक्षम नहीं हो पाता।

रियासतों का विलय

जिस समय देश आजाद हुआ, भारत मे 565 रियासते थी। ब्रिटिश सरकार ने पाकिस्तान तथा भारत को अलग-अलग स्वाधीन राष्ट्र

घोषित करने की योजना तो बना ली, परन्तु देशी रियासतों के मामले में स्पष्ट नीति की घोषणा नही की।

लॉर्ड माउण्टबेटन के सामने जब देशी रियासतो की समस्या रखी गई तो उन्हें तीन विकल्प नजर आए–

(I) वे इस समस्या का कोई समाधान न दे तथा स्वतन्त्रता के बाद रियासते अपने भविष्य का फैसला स्वय करे।

(II) नेपोलियन पद्धति द्वारा वर्तमान ईकाइयो से नए राज्यो का निर्माण करे।

(III) देशी राज्यों का विलय भारत तथा पाकिस्तान में कराने की दिशा मे कार्य करे।

पटेल, नेहरू तथा जिन्ना से बातचीत के बाद वायसराय ने दो राज्य विभागो की स्थापना की, "भारतीय राज्य विभाग तथा पाकिस्तान राज्य विभाग।" भारतीय राज्य विभाग लौहपुरुष सरदार पटेल को सौपा गया तथा राज्यो के वैधानिक मामलो की पूरी जानकारी रखने वाले वी पी. मेनन को भारतीय राज्य विभाग का सचिव नियुक्त किया गया।

5 जुलाई, 1947 को सरदार पटेल ने रियासतो के प्रति सरकारी नीति का खुलासा करते हुए एक ऐतिहासिक वक्तव्य दिया–

"हमारी खण्डित अवस्था और एक होकर मुकाबला न करने की हमारी अयोग्यता का ही परिणाम था कि भारत को आक्रमणकारियो का शिकार होना पडा .. भौगोलिक समीपता, आर्थिक, सांस्कृतिक व राजनैतिक अटूट सम्बन्धो के कारण देशी रियासतो का दायित्व है कि अवशिष्ट भारत के साथ परस्पर मैत्री व सहयोग का वातावरण बनाए रखे। यह देश अपनी परम्पराओ के साथ उन लोगो की गौरवपूर्ण विरासत है, जो इस देश मे रहते है। यह सयोग

की बात है कि इनमे से कुछ ब्रिटिश भारत मे रहते है और कुछ रियासतो मे.. .परन्तु उच्च परम्पराओं और सस्कृति मे सब बराबर के साझीदार है। हम सभी रक्त, भावनाओ और हितो की समानता से बधे है। हमे कोई भी खण्डो मे विभाजित नही कर सकता। ऐसी रुकावटे, जो पार नहीं की जा सके, हमारे बीच खडी नही की जा सकती। इसलिए मेरा सुझाव है, कि यह अच्छा हो कि हम आपस मे बैठकर मित्रों की तरह नियम निर्धारित कर ले, अपेक्षाकृत इसके कि हम विदेशियो की भाति सन्धि करे। मै अपने मित्र रियासतो के शासको और उनकी जनता को अपनी मातृभूमि के प्रति समान निष्ठा से प्रेरित होकर सबके सामन हित के लिए मैत्रीपूर्ण और सहयोग की भावना से सविधान सभा मे आने के लिए निमन्त्रित करता हू।"

सरदार पटेल के इस वक्तव्य का रियासतो के शासकों पर अच्छा प्रभाव पडा। उन्हे चट्टान से भी कठोर सरदार पटेल का हृदय मोम से भी अधिक कोमल लगा।

25 जुलाई, 1947 में चैम्बर्स ऑफ प्रिसेज का एक विशेष अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन मे लॉर्ड माउण्टबेटन ने देशी राजाओ से अपील की कि वे उस अधिराज्य में शामिल हो जाए, जिससे उनकी भौगोलिक सीमाए जुडी है।

11 अगस्त, 1947 को दिल्ली के रामलीला मैदान मे भाषण करते हुए सरदार पटेल ने देशी राजाओ से कहा, "चार दिन पश्चात् विदेशी सरकार चली जाएगी, अत· रियासते 15 अगस्त तक भारतीय सघ मे सम्मिलित हो जाए अन्यथा उनके साथ कठोर व्यवहार किया जाएगा।"

पटेल की इस चेतावनी का भारी असर हुआ और 14 अगस्त, 1947 तक हैदराबाद, जूनागढ, काठियावाड तथा कश्मीर को छोडकर

भारत की लगभग सभी रियासते भारत राज्य मे शामिल हो गई।

सरदार पटेल ने अपनी सूझबूझ और कूटनीति और आत्मीय शैली से 6 सप्ताह के अन्दर 565 मे से 561 को विलय पर विवश कर दिया। चन्द दिनो मे मिली इतनी बडी सफलता वास्तव में पटेल के विशेष व्यक्तित्व की ही देन थी।

15 अगस्त को भारत के आजाद होते ही सभी रियासतो पर से ब्रिटिश सत्ता हटा ली गई। जिन राज्यों मे सत्ता मुस्लिम शासको के हाथो मे थी अथवा जहां मुसलमानो की सख्या का अनुपात हिन्दुओ के मुकाबले बहुत ऊचा था, उन रियासतो ने भारत के साथ शामिल होने से इन्कार कर दिया। उनकी सहानुभूति पाकिस्तान के साथ थी। परन्तु भौगोलिक दृष्टि से सभी रियासते भारत की सीमा का अग थी।

ऐसी ही एक रियासत जूनागढ थी। जूनागढ़ के नवाब की सहानुभूति पाकिस्तान के साथ थी, अत कराची से 300 किलोमीटर की दूरी पर होते हुए भी उसने पाकिस्तान मे शामिल होने की जिद की, जबकि इस रियासत की 80% जनता हिन्दू थी।

15 अगस्त तक नवाब के वफादार और मुस्लिमलीग परस्त दीवान ने पटेल को धोखे मे रखा और विचाराधीन बताता रहा। 15 अगस्त को ही उसने चुपचाप अपनी रियासत का पाकिस्तान मे विलय कर दिया।

सरदार पटेल ने बडी कूटनीति से काम लिया और उन्होंने एक ओर बम्बई मे जूनागढ की अस्थाई सरकार गठित की तथा दूसरी ओर जूनागढ मे सेना भेजने का फैसला कर लिया।

27 सितम्बर को एक निर्णायक बैठक मे माउण्टबेटन ने जूनागढ के मामले को सयुक्त राष्ट्र सघ मे भेजने का प्रस्ताव रखा। यह सुनते ही सरदार पटेल बिगड गए। उन्होने नेहरू की भी नही

सुनी और मामला तुरन्त हल करने के लिए जूनागढ के चारो ओर सेना तैनात कर दी। अक्टूबर के अन्त तक अस्थायी सरकार की सेना ने पूरी रियासत पर कब्जा कर लिया। जूनागढ की सेना ने हथियार डाल दिए और जूनागढ का नवाब व दीवान नकदी और जवाहरात लेकर पाकिस्तान भाग गए।

13 नवम्बर, 1947 को वल्लभभाई पटेल काठियावाड क्षेत्र के दक्षिण पश्चिम मे स्थित जूनागढ रियासत पहुंचे। वहा की जनता ने उनका भव्य स्वागत किया। पूरे काठियावाड क्षेत्र के हिन्दू व मुसलमानों को सम्बोधित करते हुए उन्होने कहा, "जो लोग अब भी दो राष्ट्रों के सिद्धान्तो को मानते है और जिनकी हमदर्दी पाकिस्तान के साथ है, उनके लिए काठियावाड मे कोई स्थान नहीं है। जिनके मन मे हिन्दुस्तान के प्रति वफादारी नही है, वे पाकिस्तान चले जाए।"

20 फरवरी, 1948 को जूनागढ मे जनमत सग्रह कराया गया। केवल 91 लोगों ने पाकिस्तान के पक्ष मे मत दिया। 20 फरवरी, 1949 को गुजरात की सभी रियासतो को सौराष्ट्र सघ के अधीन घोषित कर दिया गया।

जूनागढ की तरह ही हैदराबाद का निज़ाम मीर उस्मान अली भी भारत मे शामिल नही होना चाहता था। वह अपने को एक स्वतन्त्र राज्य घोषित करना चाहता था। उसके साथ पटेल और माउण्टबेटन ने कई बार समझाने का यत्न किया। उसका सलाहकार सर वाल्टर मांकटन था, जो उसे भारत मे शामिल होने से रोकने में कानूनी तौर पर बहुत मदद कर रहा था।

हैदराबाद के नवाब ने भारत से पूछे बिना पाकिस्तान को 20 करोड़ का ऋण दे दिया और भारत को धमकी दी, "यदि भारतीय सघ हैदराबाद मे हस्तक्षेप करेगा तो उसे वहा 1 50 करोड हिन्दुओ

की हड्डियो और राख के अतिरिक्त और कुछ नही मिलेगा।"

उधर मामला ब्रिटेन की कॉमन सभा मे भी उठ गया। ब्रिटेन मे विरोधी दल के नेता चर्चिल ने हैदराबाद के निर्णय का समर्थन करते हुए भारत की आलोचना कर डाली। इस पर सरदार पटेल बिगड गए। चर्चिल को आडे हाथो लेते हुए उन्होने कहा, "चर्चिल एक निर्लज्ज साम्राज्यवादी है और इस समय जब साम्राज्यवाद अपनी अन्तिम सांसे ले रहा है, उसकी हठधर्मीपूर्ण बुद्धिहीनता, तर्क, कल्पना और विवेक की सीमा को पार कर रही है। इतिहास साक्षी है कि चर्चिल के अडगा नीति के कारण ही भारत तथा ब्रिटेन की मैत्री के सभी प्रयास विफल हुए।

ब्रिटिश नेताओ का भारत के आन्तरिक मामलों मे दखल देने के विरुद्ध चेतावनी देते हुए पटेल ने कहा, "ब्रिटेन यह न समझे कि भारत के नेता अनाडी है, उन्हे राज्य के पेचीदा मामले सुलझाने का अनुभव नहीं है। हम जिस मिट्टी के बने हैं, उसकी याद मत दिलाओ, वर्ना हम अपने पर आ गए तो तुम्हे लेने के देने पड जाएगे।"

हैदराबाद की समस्या बहुत बिगड चुकी थी। पाकिस्तान से चोरी छुपे हथियारे हैदराबाद पहुच चुके थे, हज़ारों कांग्रेसी कार्यकर्त्ता पकडकर जेलो मे ठूसे जा चुके थे, हिन्दू जनता पर जुल्म जारी था। कांग्रेस संगठन को अवैध घोषित कर दिया गया था और मामले को सयुक्त राष्ट्र सघ में ले जाने की तैयारी हो रही थी।

9 सितम्बर, 1948 को नेहरू के विरोध के बावजूद पटेल ने जनरल जे एल चौधरी के नेतृत्व मे 'ऑपरेशन पोलो' के लिए सेनाओ को हैदराबाद भेज दिया। भारतीय सेनाओ ने हैदराबाद की सेना के छक्के छुडा दिए। नवाब पूछ दबाकर भागा। फिर सख्ती से वहा पुलिस बल का इस्तेमाल कर सारी बिगडी हुई स्थितियो पर

काबू कर लिया गया।

जवाहरलाल नेहरू इतनी उग्र कार्यवाही के पक्ष मे न थे। परन्तु यदि ऐसी कार्यवाही न की गई होती तो हैदराबाद भारत का हिस्सा न होता।

के एम मुशी ने सरदार पटेल के हैदराबाद के प्रति रुख की सराहनी करते हुए लिखा है, "यदि जवाहरलाल नेहरू की इच्छानुसार कार्य होता तो हैदराबाद एक अलग राज्य के रूप मे भारत के पेट पर नासूर की तरह दूसरा पाकिस्तान होता।"

नेहरू जी की ढील और गलत आकलन के कारण भारत मे सबसे खतरनाक मोड केवल एक रियासत की समस्या ने लिया। वह है कश्मीर की समस्या।

शेख अब्दुल्ला के प्रभाव मे आकर नेहरू जी ने कश्मीर के मामले को सरदार पटेल के रियासत विभाग से अलग कर लिया।

ब्रिटिश सत्ता के हस्तान्तरण के समय कश्मीर नरेश महाराजा हरिसिह स्वतन्त्र कश्मीर देश की कल्पना कर बैठे। वे इतने अदूरदर्शी शासक थे कि यह भी भूल गए कि उनके राज्य मे हिन्दुओ की सख्या 40% से भी कम थी और पाकिस्तान की कश्मीर पर नजर थी।

एक और मूर्खता वे यह कर बैठे कि पाकिस्तान के साथ उन्होने यथास्थिति बनाए रखने का समझौता कर लिया और पाकिस्तान के सहयोग को स्वीकार कर लिया।

सहयोग की आड मे पाकिस्तान ने कश्मीर मे कबायलियो को उठाकर हस्तक्षेप आरम्भ कर दिया।

अक्टूबर, 1947 मे जब कबायली कश्मीर के एक हिस्से पर कब्जा कर श्रीनगर की ओर बढने लगे, तब महाराजा को अपनी गलती और गलतफहमी का अहसास हुआ। परन्तु तब तक बहुत

देर हो चुकी थी।

उन्होने भारत के वायसराय माउण्टबेटन को पत्र लिखा कि वे भारत अधिराज्य मे शामिल होने के इच्छुक है। भारत तुरन्त सैन्य बल से कश्मीर बचाने मे उनकी सहायता करे।

नेहरू जी अब भी स्पष्ट निर्णय नही ले पा रहे थे। उनका मन मामले को सयुक्त राष्ट्र सघ मे ले जाने का था। नेहरू जी का विचार था कि अन्तर्राष्ट्रीय जगत मे उनका विशेष मान है। विश्व के नेताओ को यह पता लगना चाहिए कि पाकिस्तान गांधी जी के अहिसा मूलक देश को हिसा द्वारा कितना नुकसान पहुचा रहा है।

सरदार पटेल को नेहरू जी की सोच बिल्कुल भी पसन्द नही आई। उन्होने मामले को संयुक्त राष्ट्र सघ मे ले जाने का खुला विरोध किया और कश्मीर मे सैनिक कार्यवाही कर कबायलियो को पीछे भागने पर विवश कर दिया।

परन्तु नेहरू जी नही माने। वे प्रधानमन्त्री थे और कश्मीर को विशेष राज्य के रूप मे उन्होने अपने हाथ में ले लिया था। वे सयुक्त राष्ट्र सघ चले गए और उस रियासत के मामले को अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्याय हेतु लटका आए, जिसका अधिकार महाराजा हरिसिह साफतौर पर हिन्दुस्तान को सौप चुके थे। पटेल की एक शक्तिशाली सैनिक कार्यवाही कश्मीर की समस्या को हमेशा के लिए आसानी से सुलझा सकती थी।

सरदार पटेल ने बड़े दु ख के साथ कहा था, "यदि जवाहरलाल और गोपाल स्वामी आयगर ने कश्मीर को अपना व्यक्तिगत विषय बनाकर मेरे गृह तथा रियासत विभाग से अलग न किया होता तो कश्मीर की समस्या उसी प्रकार हल होती जैसे कि हैदराबाद की।"

आजादी के बाद देश मे तेजी से परिवर्तन हो रहा था। रियासतो के विलय की समस्या को लेकर सरदार पटेल ने इतना

उग्र रूप धारण कर लिया था कि नेहरू की शान्ति नीति से उनकी टकराहट हो गई। कश्मीर की समस्या को सयुक्त राष्ट्र सघ मे उलझाने तथा कश्मीर मे पाकिस्तान के खिलाफ कठोर कदम न उठाने देने की नेहरू जी की नीति से सरदार पटेल इतनी चोट खा गए थे कि उन्होने नेहरू जी को भारत का 'सबसे पक्का मुसलमान' तक कह डाला।

हिन्दुओ के साथ हुए मुसलमानो के विश्वासघात ने उन्हे लगभग मुस्लिम विरोधी बना दिया था। वैसे राष्ट्रीय मुसलमानो के प्रति उनके दिल मे पूरी इज्जत थी, परन्तु वे हिन्दुस्तान मे रहने वाले, हिन्दुस्तान के साथ गद्दारी और पाकिस्तान के साथ वफादारी की भावना रखने वाले मुसलमानो के कट्टर विरोधी थे।

देश की समस्याओं से निरन्तर जूझने, विषम परिस्थितियो से लोहा लेने तथा अपने साथियो का पूरा सहयोग न मिल पाने, नेहरू जी द्वारा उनसे दूरी बनाए रखने की स्थिति से ससार की विशाल ताकत को अपने पैरों के नीचे रौद देने वाला वह लौहपुरुष बेहद दु खी था।

धीरे-धीरे उन्हे हृदय रोग ने दबोच लिया। 76 वर्ष की आयु मे 15 दिसम्बर, 1950 को बम्बई मे उन्होने अपना शरीर त्याग दिया।

●●●